रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

गुरुवार
03 सितंबर -2026
वर्ष 10, अंक 360
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

संक्षिप्त समाचार

भारत में ब्रिक्स सम्मेलन का सज गया मंच

दिल्ली में जुटेंगे दुनियाभर के दिग्गज, यूएन महासचिव गुटेरेस भी लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस साल अध्यक्ष होने के नाते, भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ-साथ विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि भी

शामिल होंगे। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि हमें अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करनी है कि महासचिव लगभग 10 दिनों में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में भाग लेंगे। बता दें कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। भारत के 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्च-स्तरीय बातचीत हुई हैं, ताकि ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी को तीन मुख्य आधारों पर मजबूत किया जा सके।

महुआ मोइत्रा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे दो पुलिसकर्मी

हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, सुरक्षा देनी होगी

कोलकाता (एजेंसी)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को उनके संसदीय क्षेत्र में जाने के दौरान पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि महुआ जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, उनके साथ कम से कम

दो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। यह सुरक्षा फिलहाल 30 दिनों के लिए दी गई है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। अदालत ने कहा कि महुआ को अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी तरह की परेशानी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। सांसद को अपने क्षेत्र में जाने से रोकना या उनके साथ किसी तरह का हमला अथवा दुर्व्यवहार उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि महुआ को अपने संसदीय क्षेत्र में जाने की तारीखों की जानकारी पहले पुलिस को देनी होगी।

तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन पर लगा बैन

● 5 रुपए में जमा होगा फोन, परिसर में सेल्फी और रील पर पाबंदी

वीआईपी पर भी लागू होंगे नियम, तमिलनाडु सरकार का फैसला

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह नियम मंगलवार से लागू हुआ है। नए नियम के मुताबिक, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले स्मार्टफोन काउंटर पर जमा करना होगा। इसके लिए हर फोन पर 5 रुपए चार्ज देना होगा। बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी।

मंदिर परिसर में फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के

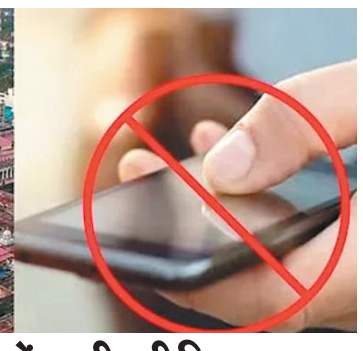

तहत वीआईपी, बड़ी हस्तियों और मशहूर लोगों की फोटो या वीडियो बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मंत्री रमेश ने यह जानकारी दी।

वीआईपी लोगों पर भी यही नियम लागू

मंदिर अधिकारियों को प्रवेश द्वार और मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लाउडस्पीकर के जरिए भी श्रद्धालुओं को इस नियम की जानकारी देने को कहा गया है। विभाग ने मंदिर परिसर में देवी-देवताओं की फोटो खींचने, वीडियो बनाने और धार्मिक अनुष्ठानों की रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगाई है।

फोटो-वीडियो और रील बनाने पर रोक

यह फैसला 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के आधार पर जारी किए गए हैं। मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं, खासकर युवाओं द्वारा फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही थीं। मंत्री ने कहा कि जिन मोबाइल फोन में कैमरा नहीं है, उन्हें मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। नए नियम का उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। कांचीपुरम के प्रसिद्ध देवराजस्वामी-अथि वरदार मंदिर में मंगलवार सुबह 6 बजे से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई। यहां फोन जमा करने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हाईकोर्ट ने तिरुचेंदूर के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। इससे पहले भी मंदिरों को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे।

राममंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा

ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड किया था, देवरिया के रहने वाले

अयोध्या (एजेंसी)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर का पहला सीईओ (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर) बनाया है। बुधवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया। देवरिया के रहने वाले जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी वायु कमान को लीड किया था। इसके अलावा बैठक में दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडेय और संघ से जुड़ीं

शिकोहाबाद की निर्मला यादव को ट्रस्टी बनाया गया है। इसके साथ ही निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बन गई हैं। 7 जून को मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था। मामले में 8 आरोपी जेल में हैं। इसी मामले में 2 जुलाई को महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद रिटायर्ड अफसर कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक अहम खबर आई है। तीन नए ट्रस्टी बनाए गए हैं। इनमें अयोध्या के मदन मोहन, दिल्ली के महेश भागचंदा और शिकोहाबाद की निर्मला यादव का नाम शामिल है। अयोध्या में मणिराम दास जी छावनी में हुई ट्रस्ट की बैठक के दौरान इन तीनों रिक्त पदों पर भर्ती हुई। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा- राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है, जिसे न्यायालय के फैसले के बाद कानूनी अधिकार है।

नेपाली पीएम शाह ने संसद में भारत को कहा धन्यवाद

बोले-सही समय पर पड़ोसी देशों ने मदद पहुंचाई, 7 दिन में 1127 मौतें

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ के मुश्किल समय में मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत के साथ-साथ चीन को भी शाह ने धन्यवाद दिया है। नेपाल में बीते महीने के आखिरी में आई बाढ़ से

भारी तबाही मची है, जिसके बाद पड़ोसी देशों ने नेपाल की दिल खोलकर मदद की है। बाढ़ के बाद कई स्तरों पर जिन देशों ने नेपाल की बढ़-चढ़कर मदद की, उसमें चीन और भारत का नाम सबसे प्रमुख है। बुधवार को नेपाल की संसद में बोलते हुए पीएम बालेन शाह ने कहा कि इतनी बड़ी आपदा के समय अंतरराष्ट्रीय मदद लेने से इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। नेपाल ने समय पर मदद पाने के लिए निजी क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ तालमेल बिठाया। भारत और चीन ने हमें मदद रहते मदद पहुंचाई, जिससे बहुत चीजें समय रहते संभव हो सकीं। नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में कहा, हमारे मित्र देशों, चीन और भारत ने टेक्नीशियन भेजे थे।

मुश्किल समय में नेपाल के साथ खड़ा रहा भारत

26 अगस्त को तिब्बत में ग्लेशियर टूटने से नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत की ओर से मदद की जा रही जहै। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को बताया कि नेपाल के लिए भारत का पांचवां राहत विमान रवाना हुआ है। यह विमान 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष बचाव उपकरणों और 5.5 टन जरूरी दवाइयों के साथ नेपाल भेजा गया है। नेपाल की मदद के लिए भारत अब तक 68 टन से अधिक राहत सामग्री और विशेष बचाव दल भेज चुका है। भेजी गई राहत सामग्री में कंबल, स्लीपिंग बैग, मजबूत तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट शामिल हैं। इसके अलावा जरूरी दवाइयां, खाद्य पैकेट, सोलर लैंप अदि भेजे हैं।

यूपी से बंगाल तक भारी बारिश का कहर

उत्तराखंड में 12 लोगों की मौत, बिहार में छाया बाढ़ का खतरा

यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे फिर धंसा, एमपी के चित्रकूट में सैलाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। नैनी झील का जलस्तर 88 फीट पार होने के बाद चैनल खोल दिए गए हैं। राज्य में 172 सड़कें बंद हैं। नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून में आज ऑरेंज अलर्ट है। पांच जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इधर, बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में गंगा-पुनपुन समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में सुबह से बारिश हो रही है। मंगलवार को तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। भागलपुर में 100 साल पुराना दुर्गा मंदिर कटाव के चलते गंगा में समा गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम सक्रिय है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश हो रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। रामघाट की करीब 400 दुकानें और 20-25 होटल डूब गए हैं। सतना में बारिश का आतंक छाया है।

दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का लोको शेड ढहा

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के लोको शेड का एक हिस्सा बुधवार को लगातार हो रही भारी बारिश के बीच ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे आठ कर्मचारी घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के प्रभावित कर्मचारियों को चिकित्सकीय उपचार दिया गया। डीएचआर के एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी कर्मचारी को गंभीर चोट नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अब तक 259 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक, 30 जून से 1 सितंबर के बीच 64 दिनों में सरकारी और निजी संपतियों को 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।

108 एम्बुलेंस सेवा का टेंडर रद्द कर एक सप्ताह में जिला स्तर पर संचालन शुरू करे सरकार : एम्बुलेंस कर्मचारी संघ

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध-भारतीय मजदूर संघ) ने राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए जारी वर्तमान टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है। संघ ने सरकार से अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार सभी जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन 8 सितंबर 2026 तक शुरू कराने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय की ओर से जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा संचालित होने से सेवा की बेहतर निगरानी, कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी राशि की बचत सुनिश्चित की जा सकती है। नीरज तिवारी ने कहा कि निजी एजेंसी के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के दौरान एम्बुलेंस के रख-रखाव, ईंधन, कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। इसका सीधा असर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है।संघ ने निजी कंपनी द्वारा कथित रूप से अवैध तरीके से सेवा से हटाए गए 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की पुनर्बहाली की भी मांग की है।

रांची समेत राज्य के शहरों का सुनियोजित विकास होगा हर वार्ड में वेंडर मार्केट की दिशा में काम : हेमन्त सोरेन

दैनिक अलग पहचान डेस्क संवाददाता, रांची/

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पथ निर्माण विभाग की कार्ययोजनाओं और संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रांची के साथ-साथ राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को भी सुनियोजित एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने पर जोर दिया। बैठक में रोड नेटवर्क, फ्लाईओवर, पार्क, चौक-चौराहे, यातायात व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, मास्टर प्लान और आगामी वर्षों की विकास कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने

कहा कि शहरों के बढ़ते विस्तार और आबादी को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक एवं समग्र विकास योजना तैयार की जाए। शहरों को जोनवार विभाजित कर आबादी और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्ययोजना बनाने का भी निर्देश दिया।सड़क के साथ ड्रेनेज भी बनेगा परियोजना का हिस्सामुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क निर्माण की योजनाओं में जल निकासी की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सड़क के दोनों किनारों पर वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाए और सड़क तथा नाली की पूरी संरचना का एकीकृत डिजाइन तैयार हो।उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पैदल यात्रियों, जल निकासी और यातायात के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त जगह का प्रावधान किया जाए। जलजमाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने का निर्देश दिया गया। पहले से बनी सड़कों पर जल निकासी की समस्या वाले क्षेत्रों का तकनीकी अध्ययन कर आवश्यक सुधार करने को भी कहा गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विभाग और संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करें तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे ठेला, गुमटी और अन्य स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका चलाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी वेंडर्स को चिन्हित कर उनके लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम किया जाए। इससे सड़क किनारे अनियोजित बाजार और दुकानों के कारण होने वाले जाम एवं भीड़ की समस्या कम होगी। साथ ही वेंडर्स की आजीविका प्रभावित किए बिना उन्हें सम्मानजनक और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाए।रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने शहर में संचालित सभी बसों की संख्या, उनके रूट और समय-सारणी का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाए।

हथिनीकुंड बैराज में डूबी सेना की बोट

2 जवान हो गए लापता, 3 जवानों को बचाया

यमुना में 15 किमी में चल रहा सर्च ऑपरेशन

यमुनानगर (एजेंसी)। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज पर अभ्यास के दौरान यमुना में बोट डूबने से लापता दो जवानों की तलाश तेज कर दी गई है। अब 15 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च अभियान चल रहा है। 10 से ज्यादा जगह सेना की टीमें झाल (पानी की गति कम करने वाले पॉइंट) पर

निगरानी कर रही हैं। दो हेलीकॉप्टर भी सर्च में जुटे हैं। जवानों के पैरों में लगे ट्रैकर से फिलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। सेना की वन पैरा स्पेशल फोर्स के अभ्यास के दौरान मंगलवार शाम करीब 5 बजे हादसा हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर से नदी में खड़ी बोट में 5 जवान कूदे थे। बोट डूबने लगी तो पांचों ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ जैकेट के साथ नदी में कूद गए। इनमें तीन जवान तैरकर पश्चिमी यमुना नहर के गेट से बाहर निकल आए। लापता जवान महाराष्ट्र के आर्यन पाटिल और जम्मू-कश्मीर के अखनूर निवासी अजय हैं। हरियाणा के साथ यूपी की एनडीआरएफ टीमें भी सर्च में जुटी हैं।

संक्षिप्त समाचार

अगर बाबूलाल मरांडी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो भाजपा छोड़ दें

रांची, एजेंसी। नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा रविवार को संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस पर लगाये आरोपों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने तीखा हमला बोला है. इरफान अंसारी ने कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आदिवासियों, दलितों की दुश्मन है. उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों की तो दुश्मन है ही, हिन्दू-मुसलमान कर ही भाजपा सत्ता में है लेकिन अब यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. अभी तो ऐसा लग रहा है कि एमएमडीआर कानून से झारखंडी मरेंगे, कटोरा लेकर भीख मांगेंगे तो बाबूलाल मरांडी को खुशी होगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी हैं, उन्हें भी लगता होगा कि बीजेपी में जाकर उन्होंने गलती की है. अगर वह सच्चे आदिवासी हैं तो राजनीतिक स्वार्थ के चलते झारखंडियों का हक और अधिकार नहीं लुटवा सकते. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून से 15000 करोड़ का नुकसान होगा, ऐसे में मंइयां सम्मान योजना, यूनिवर्सल पेंशन सहित कई योजनाएं रुक जाएंगी, क्या बाबूलाल मरांडी यही चाहते हैं.

गुमला में बस की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत, एक जख्मी

गुमला, एजेंसी। जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह दुर्घटना डुमरी-चैनपुर मार्ग पर अल्फोंस बागान के समीप एक बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर के कारण हुई. घायल युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में चल रहा है. मृतकों की पहचान जूरमु गांव के रनवीर खेरवार और हिसरी गांव के प्रिंस पोल तिग्गा के रूप में हुई है. घायल युवक नौहट्टा गांव का अक्षय कुजूर है. तीनों की उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है. घटना के बारे में जानकारी देते हुए डुमरी थाना प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि दुर्घटना में बस को पुलिस ने जब्त करके चेकपोस्ट में रखा है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. जानकारी के अनुसार, तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर चैनपुर कॉलेज से लौट रहे थे. खीस्तनगर स्थित बागान के पास उल्टी दिशा से आ रही बस से उनकी बाइक की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अक्षय कुजूर को सिर और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं. दुर्घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने जैरागी के पास बस को पकड़कर जब्त कर लिया है और उसे हुटाप पिकेट में रखा गया है. राहगीरों की सूचना पर डुमरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी भेजा और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

पलामू में सोन नदी खतरे के निशान से ऊपर, तटवर्ती क्षेत्रों में रखी जा रही है निगरानी

पलामू, एजेंसी। पलामू में सोन नदी खतरे के निशान को पार कर गई है. बुधवार की सुबह 6:00 बजे पलामू के हुसैनाबाद में सोन नदी खतरे के निशान 208 सेंटीमीटर अधिक थी. दरअसल, सोन नदी पर उत्तर प्रदेश के रिहंद के इलाके में बने डैम का गेट खोला गया है. जिसके कारण जलस्तर बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है. सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तरी कोयल भी पूरी तरह से उफान पर है. इस कारण सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सोन नदी पलामू के हैदरनगर और हुसैनाबाद प्रखंड से होते हुए बिहार के इलाके में दाखिल हो जाती है. सोन नदी के डीला (नदी की दो धाराओं के बीच का स्थान)में बड़ी संख्या में आबादी रहती है, जिन्हें प्रशासन ने बाहर निकाल लिया है.

एसबीयू के विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

दैनिक अलग पहचान,
डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची।सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के प्लेसमेंट विभाग की ओर से वर्ष 2027 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आगामी कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयार करना तथा उन्हें कॉर्पोरेट जगत की कार्यप्रणाली, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से परिचित कराना था। कार्यक्रम में बी.टेक. की सभी शाखाओं, एमसीए, एमबीए, एम.कॉम., बीबीए, बी.कॉम., बीबीए-एसबीपीएम, बीसीए, सभी शाखाओं के डिप्लोमा, बीए एवं एमए अंग्रेजी तथा बीए एवं एमए अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों ने भाग लिया।कार्यक्रम की शुरुआत प्लेसमेंट विभाग द्वारा आयोजित सत्र से हुई। इसमें विद्यार्थियों को प्लेसमेंट प्रक्रिया, आवश्यक दिशा-निर्देश, कंपनियों की चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार की तैयारी तथा करियर निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को समय रहते अपनी तैयारी शुरू करने तथा प्लेसमेंट के लिए गंभीरता से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। टेकफोकस के वरिष्ठ तकनीकी प्रमुख- क्लाउड निखिल उपाध्याय ने क्लाउड समाधान, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, जनरेटिव एआई और एलएलएम जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बदलती तकनीक के साथ अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल को लगातार बेहतर बनाने की सलाह दी।टेकफोकस के वरिष्ठ सेल्सफोर्स विकास विशेषज्ञ श्री अदनान अंसारी ने सेल्सफोर्स विकास, एपेक्स, एलडब्ल्यूसी, ट्रिगर्स, सेल्सफोर्स एकीकरण और व्यावसायिक प्रक्रिया स्वचालन जैसे विषयों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को सेल्सफोर्स के निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण मंच 'ट्रेलहेड' का उपयोग करने तथा संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।प्रबंधन और वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए इंडसइंड बैंक की क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रबंधक सुश्री प्राची महतो के साथ उद्योग संवाद सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि कंपनियां नए स्नातकों से क्या अपेक्षा रखती हैं और कॉलेज से कॉर्पोरेट जीवन में प्रवेश के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने का झारखंड ने पेश किया रोड मैप

दैनिक अलग पहचान,
डेस्क संवाददाता, रांची

रांची: जल जीवन मिशन के समापन सत्र में झारखंड ने जल संरक्षण, सिंचाई क्षमता के विस्तार और जल परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर राज्य की रणनीति और भविष्य की प्राथमिकताओं का रोडमैप प्रस्तुत किया। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में झारखंड की ओर से जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हिस्सा लिया। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में करीब 30 प्रतिशत वन क्षेत्र और पठारी भू-भाग है। ऐसे में वर्षा जल का प्रभावी संचयन बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य में होने वाली करीब 80 प्रतिशत वर्षा का पानी बह जाता है। सरकार का लक्ष्य इस पानी को रोककर संरक्षित करना और वर्षभर उपयोग में लाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 24.25 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की संभावना है, जबकि अब तक लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षमता ही विकसित हो सकी है। अब सरकार का जोर नई परियोजनाएं शुरू करने के साथ-साथ मौजूदा सिंचाई संरचनाओं का अधिकतम और प्रभावी उपयोग करने पर है। नहरों के जरिए पानी पहुंचाने के दौरान होने वाले रिसाव को कम करने और खेतों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पटमदा-बोड़ाम और नीमडीह-कुकडू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं तथा पलामू के अमानत बराज के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है। सम्मेलन में जलाशयों की गाद निकासी, तालाबों और आहरों के जीर्णोद्धार तथा बाढ़ और सूखा प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके लिए रियल-टाइम सूचना प्रणाली, फोरकास्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्विन जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हफीजुल हसन ने कहा कि विभिन्न राज्यों के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान देश की जल सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से राज्य को जल-सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रिम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट की सुविधा, 15 दिनों में शुरू करने का अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

रांची, एजेंसी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न डिजिटल एवं तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की.

इस बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन,आईसीयू, एचएमआईएस,सीसीटीवी एवं डैशबोर्ड तथा एचआरआईएस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की. बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव के साथ साथ सी-डैक, बीएसएनएल, भारतीय स्टेट बैंक एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

सी-डैक के एचएमएस की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सिस्टम को अपडेट करने तथा रिम्स जाकर इसकी प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्वयं भी रिम्स जाकर डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रगति देखने की बात कही. उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट की सुविधा 15 दिनों के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया. बीएसएनएल को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. पीएचसी स्तर पर इंटरनेट की गति को 2 एमबीपीएस से बढ़ाकर 20 एमबीपीएस करने का लक्ष्य है. बीएसएनएल ने बताया कि 188 सीएचसी में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. रामगढ़ में 07 सितंबर तक सभी पीएचसी में 20 एमबीपीएस वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. बिजली की समस्या वाले केंद्रों पर 48 घंटे का बैकअप देने की व्यवस्था की जा रही है. इस बैठक में टेली-ईसीजी मशीन का प्रदर्शन भी किया गया, छोटी और एआई आधारित इस मशीन को सीएचसी स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है. इससे गोल्डन आवर में तत्काल ईसीजी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के साथ मोबाइल के माध्यम से भी रिपोर्ट देखी जा सकेगी. इसके अलावा 104 पोर्टल के माध्यम से संचालित ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचआरआईएस) की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई. 104 परियोजना के निदेशक ने विकसित विभिन्न मॉड्यूल, उनकी कार्यप्रणाली, प्रगति और आगामी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया. अपर मुख्य सचिव ने सिस्टम की शीघ्र समीक्षा कर आवश्यक सुधार एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया. उन्होंने एनएचएम के संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान को एचआरआईएस पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापित मासिक उपस्थिति से जोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया.

मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का रांची में शुभारंभ

दैनिक अलग पहचान,
डेस्क संवाददाता, रांची

रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची 2026' का बुधवार को राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, रांची में शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में नागरिकता, वैश्विक अनुभवों, तकनीक, जागरूकता, लैंगिक समानता, प्रवासन और मतदाता सूची प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने मंथन किया।उद्घाटन सत्र में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो. सारंग मेधेकर, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल तथा संत जेवियर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर सहित शिक्षाविद्, शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ मौजूद रहे।के. रवि कुमार ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण से आगे बढ़कर मतदाता पंजीकरण के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर व्यापक विमर्श करना है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के लिए 800 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से संपर्क किया गया, जिससे 230 शोध-सार प्राप्त हुए। स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति ने इनमें से 80 शोध-सार को लघु सूचीबद्ध किया और 58 शोध-पत्रों का चयन किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रबंधन के व्यावहारिक अनुभवों और अकादमिक शोध का समन्वय मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, समावेशी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में सहायक होगा। कुलपति प्रो. अशोक आर. पाटिल ने कहा कि शुद्ध एवं नियमित रूप से अद्यतन मतदाता सूची लोकतांत्रिक सहभागिता का प्रवेश द्वार है। वहीं प्रो. सारंग मेधेकर ने तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से निर्वाचन प्रबंधन में पैदा हो रही नई संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

छात्र संगठनों के प्रदर्शन से लेकर क्यूआर कोड स्कैनिंग तक, 9 सितंबर को डीजीपी करेंगी पुलिसिंग का 'रियलिटी चेक'

रांची, एजेंसी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिलों में पुलिसिंग और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है. 9 सितंबर 2026 को डीजीपी झारखंड तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक होगी. इसमें राज्य के सभी जिलों से लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट ली जाएगी. आईजी अभियान के पत्र के अनुसार बैठक में खास तौर पर सीजेपी/छात्र संगठनों की ओर से पिछले दिनों किए गए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान जिलों की ओर से की गई विधिक कार्रवाई की समीक्षा होगी. पुलिस मुख्यालय यह देखेगा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में जिलों ने किस तरह की कानूनी कार्रवाई की और उसकी प्रगति क्या है. पत्र में सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है की वे इस संबंध में पीपीटी भी तैयार करे. समीक्षा बैठक में बीट पुलिसिंग के दौरान की स्थिति भी प्रमुख एजेंडे में शामिल है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों से यह जानकारी ली जाएगी कि बीट स्तर पर पुलिसकर्मी क्यूआर कोड स्कैनिंग की व्यवस्था का कितना प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. बैठक में मालखाने की स्थिति और निस्तारण के लिए लंबित मामलों को भी एजेंडे में रखा गया है.

जेपीएससी-जेएसएससी विवाद पर बीजेपी का हेमंत सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम

रांची, एजेंसी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अब भाजपा ने सरकार के सामने तीन बड़ी मांगें रखी हैं. भाजपा ने इन मांगों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी.

इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मीडिया के सामने ज्ञापन देने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के मार्ग पर राज्य सरकार के सामने तीन मांग रखी गई हैं. पहली मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की अलग-अलग परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराई जाए. पार्टी का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच जरूरी है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके. दूसरी बड़ी मांग छात्रों के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज स्नढ्ढक्र को तत्काल रद्द करने की है. भाजपा के मुताबिक, परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों ने करीब एक महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था. पार्टी का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए।. ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज स्नढ्ढक्र को रद्द करने की व्यवस्था की गई है. भाजपा ने इसी आधार पर झारखंड में भी छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने की मांग की है. जेपीएससी से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर है. पार्टी ने कहा है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मामले में समान रूप से दोषी माने जा रहे अन्य तीनों पूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए. भाजपा का तर्क है कि अगर जांच में सभी की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई भी समान रूप से होनी चाहिए. मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन तीन मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 48 घंटे का समय है. अगर इस अवधि में मांगें पूरी नहीं की गईं तो प्रदेश भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी.

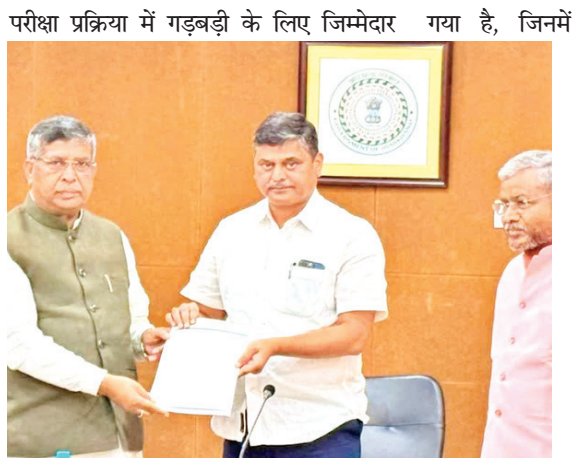

एंथे 2026 लॉन्च: छात्रों की प्रतिभा परखेगा आकाश, 100% तक स्कॉलरशिप और आरएस2.5 करोड़ कैश प्राइज का मौका

16 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक छात्रों का भरोसा, एंथे 2026 देगा तैयारी और क्षमता का सटीक आकलन

दैनिक अलग पहचान,
डेस्क संवाददाता,रांची/

रांची : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी क्षमता, मजबूतियों और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान कराने के उद्देश्य से आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) 2026 लॉन्च किया है। पिछले 16 वर्षों में एंथे के लिए 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रमणि सिंह, उपाध्यक्ष, आकाश इंस्टीट्यूट, डॉ. नवीन गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर, उदित सिंह, डिप्टी ब्रांच हेड और प्रीतम कुमार, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी। एंथे को केवल स्कोर आधारित परीक्षा के बजाय वैज्ञानिक और व्यापक डायग्नोस्टिक असेसमेंट के रूप में तैयार किया गया है। परीक्षा में विद्यार्थियों की कॉन्सेप्ट समझ, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी और टेस्ट के दौरान व्यवहार का आकलन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को विस्तृत 'एंथे इंटेलिजेंस रिपोर्ट' मिलेगी, जिसमें विषयवार प्रदर्शन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस पोटेंशियल (सीएसपी), टेस्ट-टेकिंग पर्सनैलिटी (टिप) और अटेम्प्ट इंटेलिजेंस कोशिएंट (एक) का विश्लेषण होगा। एईएसएल के एमडी एवं सीईओ चंद्र शेखर गरिसा रेड्डी ने कहा कि एंथे का उद्देश्य केवल स्कॉलरशिप देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक अकादमिक क्षमता और तैयारी की स्थिति समझने में मदद करना है। एंथे 2026 में पात्र छात्रों को 100% तक स्कॉलरशिप और टॉप परफॉर्मर्स को कुल आरएस2.5 करोड़ के कैश प्राइज दिए जाएंगे। कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन परीक्षा 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तथा ऑफलाइन परीक्षा 11 और 25 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

संक्षिप्त समाचार

रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 18 कोचिंग संस्थानों पर निगम का शिकंजा

रांची, एजेंसी। नगर निगम ने बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. निगम की विशेष जांच टीम ने शहर के अलग-अलग वार्डों में संचालित 70 कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस की जांच की. जांच में 18 संस्थान ऐसे मिले, जो बिना वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे. नोटिस के बावजूद लाइसेंस नहीं लेने पर अब इन संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. निगम के अनुसार, कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की वैधानिक स्थिति की जांच के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत 70 संस्थानों की जांच की गई। इनमें 18 संस्थानों में ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया. निगम ने पहले ही संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने और नियमानुसार संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया था. निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी संबंधित संस्थानों की ओर से आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया. इसके बाद निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई शुरू की है. निगम के मुताबिक, आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है. जांच में संबंधित 18 संस्थानों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 तथा झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 और 20 के उल्लंघन का मामला सामने आया है. निगम की ओर से अब इन संस्थानों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. जिन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और षष्टक्ष्य क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं. रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमतियां प्राप्त कर ही संचालन करने की अपील की है.

झारखंड में जरूरत वाली बीजों की आपूर्ति पर जोर, कृषि निदेशक ने दिए कई निर्देश

रांची, एजेंसी। झारखंड में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और बीज आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कृषि विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं. कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज की अध्यक्षता में 1 सितंबर 2026 को हुई बैठक में बीज नीति के संदर्भ में कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद दिशा-निर्देश जारी किए गए. इस बैठक में तय किया गया कि राज्य में काम कर रहे बीज आपूर्तिकर्ता संस्थानों में राज्य कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और गैर-सरकारी संस्थानों को जरूरत के आधार पर बीज उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य राज्य में किसानों की मांग के अनुरूप बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है. विभाग ने दलहन मिशन योजना के तहत बीज की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है. आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समेत संबंधित संस्थानों से बीज प्राप्त करने के लिए एकरारनामा किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए एनएससी को एकरारनामा का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. बीज आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी बीज आपूर्तिकर्ता संस्थानों को भारत सरकार के 'साथी पोर्टल' पर बीज का आधार, प्रमाणित बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसके स्रोत से जुड़ी जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने को कहा गया है.

अजय सिंह की विदाई से अनुराग गुप्ता की वापसी और तदाशा मिश्रा की ताजपोशी तक, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रखा पक्ष

रांची, एजेंसी। झारखंड की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे में तदाशा मिश्रा की डीजीपी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे की परिस्थितियों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि तदाशा मिश्रा की नियुक्ति मनमाने तरीके से नहीं हुई, बल्कि राज्य में लागू नियमों और चयन प्रक्रिया के तहत की गई है.

सरकार ने हलफनामे में वर्ष 2024 से लेकर तदाशा मिश्रा की नियमित डीजीपी के रूप में नियुक्ति तक का पूरा घटनाक्रम बताया है. इसमें तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह के पद पर बने रहने को लेकर सामने आई स्थिति, विधानसभा चुनाव के दौरान डीजीपी में बदलाव, यूपीएससी से पैनल मिलने में हुई देरी और बाद में राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों का उल्लेख किया गया है.

सरकार के अनुसार, वर्ष 2024 में

तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पद पर बने रहने में अपनी असमर्थता या अनिच्छा जताई थी. इसके बाद राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार सीआईडी के तत्कालीन डीजी अनुराग गुप्ता को सौंपा गया. उसके बाद नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने यूपीएससी को नया पैनल तैयार करने का प्रस्ताव भी भेजा.

इसी दौरान यूपीएससी ने अजय कुमार सिंह को निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए जाने के कारणों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा. इसी के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई. चुनाव के दौरान आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों के कारण डीजीपी के पद पर फिर बदलाव हुआ. अनुराग गुप्ता को पद के प्रभार से हटाकर अजय कुमार सिंह को चुनाव अवधि तक डीजीपी की जिम्मेदारी दे दी गई. चुनाव समाप्त होने के बाद 28 नवंबर 2024 को अनुराग गुप्ता को फिर से डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच यूपीएससी के साथ लगातार पत्राचार किया गया, लेकिन नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल उपलब्ध नहीं हो सका. इसके बाद राज्य सरकार ने डीजीपी के चयन और नियुक्ति के लिए नए नियम तैयार किए. ष्ठजनवरी 2025 में राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली. इन नियमों के तहत डीजीपी के चयन के लिए छह सदस्यीय चयन/नामांकन समिति बनाई गई. इस समिति में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावा यूपीएससी के नामित अधिकारी, जेपीएससी के नामित अधिकारी, पूर्व डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव को समिति में शामिल किया गया.

नए नियम लागू होने के बाद 21 जनवरी 2025 को चयन/नामांकन समिति की बैठक हुई. समिति ने डीजी रैंक के तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा.

रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, निचले इलाकों में घुसा पानी

रांची, एजेंसी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय डिप्रेशन और कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में लगातार बारिश हो रही है. पिछले कई घंटों से रांची में हो रही बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है. सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. लगातार बारिश के कारण शहर के पंचशील नगर, पंडरा डैम, हरमू आनंद नगर और निवारणपुर समेत हरमू नदी के आसपास के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. कई जगहों पर सड़कें भी जलमग्न हो गई, जिससे पैदल चलने वालों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. पंचशील नगर निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि देर रात तक हुई तेज बारिश के कारण उनके घर में पानी घुस गया था. अचानक पानी बढ़ने से परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

हजारीबाग में आदिम जनजाति बिरहोर को छात्रों की टोली ने दी मच्छरदानी, केक काटकर मनाया जन्मदिन

हजारीबाग, एजेंसी। बिरहोर आदिम जनजाति जिसे संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है. जो विलुप्त होती हुई जनजाति को संरक्षित करने के लिए अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं. काम कर रहे हैं. छात्रों की टोली जिले के चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में जाकर आदिम जनजाति के लोगों को मच्छरदानी भेंट की है.

छात्रों का कहना है कि मलेरिया और डेंगू से इन्हें बचाने के लिए

यही नहीं उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, इसको लेकर उन्हें शिक्षित किया जा रहा है. बिरहोर टांडा में पहली बार किसी बिरहोर ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया. वहीं बिरहोर को मलेरिया और डेंगू से बचाने के लिए मच्छरदानी भेंट की गई.

हजारीबाग के कई छात्र इन दिनों विलुप्त होती हुई आदिम जनजाति बिरहोर को संरक्षित करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मच्छरदानी दी गई है, साथ ही प्रेरित भी किया है कि सोने से पहले मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें. छात्रों की टोली ने अपना नाम 'अर्थ एक प्रयास' रखा है. इसके सदस्य बताते हैं कि अपनी पॉकेट मनी और कुछ लोगों से मदद लेकर बिरहोर परिवार के लोगों को मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है. साथ ही उन्हें यह भी बताया गया है कि हर रात मच्छरदानी लगाकर सोए.

छात्रों के प्रयास की सराहना स्थानीय थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने भी की हैं. जब बिरहोर परिवार के सदस्यों को छात्रों द्वारा मच्छरदानी भेंट की जा रही थी, तो चुरचू थाना प्रभारी अश्वनी कुमार भी पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये छात्रा प्रेरणा के स्रोत है, जो अपने पॉकेट मनी से बिरहोर परिवार के लोगों को मदद कर रहे हैं.

थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत पड़े तो निस्संकोच मदद करने का अवसर प्रदान करें. बिरहोर परिवार के लोगों को मदद पहुंचाना खुशी की बात होगी. इन्होंने 'अर्थ एक प्रयास' के सभी सदस्यों को उनके काम के लिए धन्यवाद भी दिया है.

यही नहीं बच्चों की ओर से पहली बार बिरहोर बच्चे का जन्मदिन मनाया गया. बिरहोर बच्चों की जन्मदिन के अवसर पर केक काटा गया और लोगों ने उसे शुभकामना दी. दूसरी ओर मच्छरदानी मिलने पर खुशी जाहिर की. साथ ही उन्होंने कहा कि अब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी नहीं होगी. हजारीबाग के ये छात्र, समाज के दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो समर्थवान हैं, वे दूसरों की मदद जरूर करें, तभी देश और समाज विकासशील से विकसित होगा.

तीन विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क बनी 'डेथ ट्रैप'! लोगों का पैदल चलना मुश्किल, पांच साल पहले हुआ था निर्माण

लातेहार, एजेंसी। लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक से डेमू होते हुए लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बदहाल हो गई है. कभी हजारों लोगों के सुगम आवागमन का जरिया रही यह सड़क अब हादसों को न्योता दे रही है. सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. दो जिलों और तीन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क अब लोगों के लिए 'डेथ ट्रैप' बनती जा रही है.

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक से सदर प्रखंड के डेमू पंचायत होते हुए लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली इस अति महत्वपूर्ण सड़क की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है कि यहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. यह सड़क लातेहार जिले के मनिका विधानसभा, लातेहार विधानसभा और लोहरदगा जिले के लोहरदगा विधानसभा को जोड़ती है. जिससे कम से कम 25000 से अधिक लोगों का आवागमन होता है.

वर्तमान में इस सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं. कई हिस्सों में सड़क की पिच पूरी तरह उखड़ गई है. बारिश

होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों के लिए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि आगे सड़क है या गहरा गड्ढा. ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ छोटे वाहन चालकों को बना रहता है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि रोजाना हजारों लोग इसी सड़क से होकर बाजार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए आवाजाही करते हैं. सड़क की बदहाली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

स्थानीय लोग बताते हैं कि इस सड़क का निर्माण लगभग 5 साल पहले कराई गई थी. परंतु निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी निम्न थी कि बनने के बाद से ही सड़क की स्थिति खराब होने लगी थी. वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. स्थानीय निवासी उत्तम कुमार बताते हैं कि हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. प्रत्येक दिन कोई न कोई दुर्घटना यहां होती रहती है. सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने के कारण बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है.

वहीं, परमेश्वर यादव बताते हैं कि उन्हें दूध बेचने के लिए सुबह शाम लातेहार जाना पड़ता है. मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए. उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां तो यहां अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. जो यहां के स्थानीय निवासी हैं उन्हें तो सड़क में बने गड्ढों की जानकारी रहती है लेकिन जो अनजान लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, वे अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं.

सलाखों के पीछे बदल रही जिंदगी, कैदियों के बनाए उत्पाद पहुंचे रहे हाईकोर्ट और विधानसभा!

रांची, एजेंसी। कभी जिन हाथों में अपराध का दाग था, वही हाथ अब हुनर गढ़ रहे हैं. सलाखों के पीछे रहकर वो अपने आप को अपराध से दूर हुनर की आग तपाकर कुंदन की तरह निखरने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं. कभी सलाखों के पीछे सजा काटने वाले कैदी अब जेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फर्नीचर बना रहे हैं, करघे पर कपड़े बुन रहे हैं, फाइल और प्रिंटिंग बनाने का काम कर रहे हैं, साबुन-फिनाइल तैयार कर रहे हैं और बेकरी में ब्रेड, बिस्किट और केक बना रहे हैं. इनमें खास बात यह है कि इनके हाथों से तैयार सामान अब जेल की चारदीवारी से बाहर निकलकर झारखंड हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट, विधानसभा और दूसरे सरकारी संस्थानों तक पहुंच रहे हैं.

जेल का नाम सुनते ही आमतौर पर सलाखें, बंद कमरे और कैदियों की दुनिया का ख्याल आता है. झारखंड की जेलों में अब इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है. यहां कैदियों को केवल बंद रखने तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें काम के जरिए हुनर सिखाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी जोड़ा जा रहा है.

जेलों में संचालित जेल उद्योग के तहत कैदी हैंडलूम पर कपड़ा बुनने से लेकर सिलाई, जूट मैट बनाने, फर्नीचर और अलमारी तैयार करने, साबुन-फिनाइल बनाने, प्रिंटिंग, बेकरी और डेयरी जैसे कामों में हाथ आजमा रहे हैं. जेल उद्योगों से तैयार उत्पादों को 'मुक्ति'

ब्रांड के तहत बाजार में उतारने की व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा की गई है. इसका उद्देश्य जेल के भीतर कैदियों को रचनात्मक और उपयोगी काम से जोड़ना, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और काम के बदले आजीविका के रूप में मजदूरी उपलब्ध कराना है.

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि झारखंड की जेलों में तैयार किए जा रहे सामान की सप्लाई अब केवल जेल विभाग तक सीमित नहीं है. झारखंड हाईकोर्ट, राज्य के लगभग सभी व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) और झारखंड विधानसभा को जेल उद्योगों में तैयार सामान की आपूर्ति की जा रही है. इसके अलावा जिला पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य सरकारी संस्थानों से भी जेल में बने उत्पादों की मांग मिल रही है.

जेल आईजी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट से हाल ही में जेल में तैयार फर्नीचर की सप्लाई का ऑर्डर मिला है. मांग के अनुसार जेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में फर्नीचर और अन्य सामान तैयार कर संबंधित संस्थानों को उपलब्ध कराया जा रहा है.

झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के लगभग सभी व्यवहार न्यायालयों से जेल उद्योगों में तैयार सामान की मांग है. हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जेल में तैयार फर्नीचर की सप्लाई का ऑर्डर भी मिला है. यानी जिस व्यवस्था में कैदी सजा काट रहे हैं, उसी व्यवस्था में उनके हाथों तैयार हुआ फर्नीचर अब न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण संस्थानों में इस्तेमाल होगा.

ल आईजी के मुताबिक, जेल उद्योगों में तैयार सामान की मांग अब सिर्फ जेल विभाग तक सीमित नहीं रह गई है. हाईकोर्ट और राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट से भी सामान की मांग आ रही है. मांग के अनुरूप जेल प्रशासन उपलब्ध क्षमता के आधार पर सामान तैयार कर उसकी आपूर्ति कर रहा है. यह बदलाव जेल सुधार की उस सोच को मजबूती देता है, जिसमें कैदी को केवल अपराध की सजा देने तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उसे ऐसा कौशल देने पर जोर दिया जाता है. जिससे वह जेल से बाहर निकलने के बाद सम्मानजनक तरीके से अपनी आजीविका चला सके.

जेल उद्योगों के उत्पादों की पहुंच विधानसभा तक भी है. जेल आईजी के अनुसार, झारखंड विधानसभा को भी जेल में तैयार सामान की आपूर्ति की जा रही है.

झरिया मास्टर प्लान की पीएम के सलाहकार ने की समीक्षा, पुनर्वास और बेलगड़िया शिफ्टिंग में तेजी के निर्देश

धनबाद, एजेंसी। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि बेलगड़िया टाउनशिप के फेज-1, 2 और 3 में अधिग्रहित 3,737 आवासों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवासों में रूफ वाटरप्रूफिंग, फर्श और बाथरूम में टाइल्स, पुट्टी एवं वेदर कोट पेंटिंग तथा पीवीसी पानी की टंकियां लगाने का काम प्रस्तावित है. कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईआईटी-आईएसएम के साथ एमओयू किया गया है और संस्थान के प्रमाणन के बाद ही भुगतान की व्यवस्था रखी गई है.

प्रशासन के अनुसार, पुनर्वासित परिवारों को 99 साल का लीज अधिकार दिया जाएगा. बीसीसीएल बोर्ड की ओर से स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क को माफ करने अथवा वहन करने का निर्णय लिया गया है. बेलगड़िया में प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन पूरा हो चुका है, जबकि डीएमएफटी के माध्यम से जी+2 मिडिल स्कूल और आमटाल हाई स्कूल का निर्माण चल रहा है. आरएसपी कॉलेज के नए भवन तथा मल्टीपर्पस हॉल के विस्तार के लिए भी टेंडर जारी किया जा चुका है.

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हेल्थ सब-सेंटर को एल-1 स्तर पर विकसित किया गया है और एनक्यूएएस मानकों को लागू किया गया है. 24 घंटे एंबुलेंस

सुविधा के साथ 20 बेड वाले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी जारी है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेलगड़िया में पुलिस पोस्ट संचालित है, जबकि पूर्ण थाना स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. टाउनशिप में सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है.

बैठक में सड़क, बिजली और जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा हुई. बारमसिया-कुसमाटांड़ मुख्य सड़क और पलानी मोड़ सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया है. चार लेन झरिया रिंग रोड की व्यवहार्यता रिपोर्ट एनएचएआई तैयार कर रहा है. दामोदर नदी से स्थायी जलापूर्ति योजना पर काम आगे बढ़ रहा है. सीवरेज व्यवस्था के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का डीपीआर नमामि गंगे को भेजा गया है. बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 33 केवी सब स्टेशन और स्मार्ट मीटरिंग की योजना पर काम चल रहा है. बेलगड़िया में 500 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं. इसके अलावा 2 और 4 मेगावॉट क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रस्ताव तैयार किया गया है. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने की योजना है. हिंडाल्को, राजधानी टेक्सटाइल्स और संबंधित संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हो चुका है. इससे 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. आदित्य बिड़ला समूह के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी जारी है. युवाओं को ढ्ढ, डेटा साइंस और कोडिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के साथ प्लेसमेंट ड्राइव और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. आरएसपी कॉलेज और करमाटांड़ में बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल 200 विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की व्यवस्था शुरू की गई है.

दूसरे राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टर अब झारखंड में देंगे सेवा- मंत्री इरफान अंसारी

जमशेदपुर, एजेंसी। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पतालों में इलाज की समस्या को लेकर विभाग पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी चिकित्सकों को अच्छी सैलरी देने के बाद भी नहीं आ रहे थे. अगर कोई डॉक्टर आ भी जाता था तो कुछ समस्या की वजह से भाग जा रहे थे. इसलिए सरकार ने बैंगलुरु, तमिलनाडु और केरलम से विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाने का फैसला लिया है. ताकि राज्य के प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जा सके.

मंत्री ने कहा कि इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम उन प्रदेशों में जाकर डॉक्टरों से बात करेगी और लगभग 2 हजार चिकित्सकों को झारखंड में सेवा देने के लिए आमंत्रित करेंगे. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें संबंधित राज्यों में जाकर डॉक्टरों से संपर्क कर रही है. अब सवाल है कि आखिर झारखंड के चिकित्सकों की क्या समस्या है कि सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. साथ ही सरकार द्वारा राज्य की जगह दूसरे प्रदेशों से विशेषज्ञ डॉक्टरों को नौकरी के लिए क्यों बुलाई जा रही है.

पूर्वी सिंहभूम जिला के दौरे पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जमशेदपुर में राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी. बिस्टुपुर स्थित सर्किट हॉउस मे मंत्री ने बताया की जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल की समस्या को दूर करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं. अस्पताल में मरीज के अलावा अब अन्य लोगों का प्रवेश नहीं होगा. उन्होंने कहा की निजी अस्पताल में कई खामियां होती है, घटनाए घटती है, लेकिन सुर्खियों में सिर्फ सरकारी अस्पताल ही रहता है.

उन्होंने बताया की चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए केवल अस्पतालों के भवन और अत्याधुनिक मशीनें ही नहीं, बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, मेडिकल शिक्षा का विस्तार, आधुनिक जांच सुविधाएं, डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर एक साथ काम किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है. जिसमें 400 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि विस्तार योजना पूरी होने के बाद एमजीएम अस्पताल में पीजी की सीटों की संख्या बढ़ाकर 150 और एमबीबीएस की सीटें 250 तक करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि रिम्स रांची के साथ-साथ राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मेडिकल शिक्षा के विस्तार से आने वाले वर्षों में राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. मंत्री ने बताया की डिजिटल हेल्थ सिस्टम में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है.

संक्षिप्त समाचार

बिहार सरकार के अधिकारी को सशर्त वीआरएस की मंजूरी

पटना, एजेंसी। बिहार सचिवालय सेवा के एक अधिकारी को एक खास शर्त के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह मंजूरी विधु भूषण मिश्रा को दी गई है। वे अभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर विधु भूषण मिश्रा ने बीआरएस के लिए 18 मई, 2026 और 22 जून, 2026 को आवेदन किया था। उनके आवेदन के मद्देनजर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 6 जुलाई को सिफ़ारिश की। इस सिफ़ारिश के बाद, मामले की रिपोर्ट आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को भेजी गई। इसके बाद, वित्त विभाग ने 27 अप्रैल, 1979 के नियमों के तहत 31 अगस्त, 2026 से लागू होने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी। हालांकि इस मंजूरी के साथ एक शर्त भी लगाई गई है। शर्त ये हैं कि विभाग की ओर से अधिकारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उनके सेवांत लाभ (सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ) से वसूला जाएगा। विभाग के मुताबिक कुल रकम 12,32,397 रुपये अधिकारी के अंतिम भुगतान (सेटलमेंट) से एकमुश्त काट ली जाएगी। यह आधिकारिक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मनोज कुमार के हस्ताक्षर वाले पत्र के जरिए जारी किया गया है। पत्र में उप सचिव मनोज कुमार ने साफ किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया 12,32,397 रुपये का अतिरिक्त भुगतान और अन्य बकाया राशि, टर्मिनल बेनिफिट्स से एकमुश्त काट ली जाएगी। ऐसे सेवानिवृत्ति मामलों में, सभी बकाया राशि का निपटारा विभाग खुद करता है।

बिहार की सरकारी शिक्षिका ने की आत्महत्या! पति के दोस्त ने खोले कई राज

वैशाली, एजेंसी। बिहार के वैशाली में एक बीपीएससी शिक्षिका की मौत से सनसनी फैल गई है। चेहराकलां प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित 27 वर्षीय बीपीएससी शिक्षिका की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षिका का शव विद्यालय से लगभग 200 मीटर दूर स्थित उनके किराए के कमरे से बरामद किया गया है। रात करीब 11 बजे पति द्वारा फोन नहीं उठाए जाने पर मकान मालिक ने जब कमरे की खिड़की से झांककर देखा, तब इस घटना का पता चला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कटहरा थाना पुलिस ने अंदर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षिका शनिवार को विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के बाद दोपहर करीब एक बजे अपने किराए के कमरे पर लौटी थीं। शाम के वक्त उनके पति ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद पति ने मकान मालिक ललन श्रीवास्तव को फोन कर मधु से बात कराने का अनुरोध किया। जब मकान मालिक कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बार-बार आवाज देने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद खिड़की से झांककर देखने पर मकान मालिक होश उड़ गए। शिक्षिका के अकेले चेहराकलां लौटने और उसी दिन विद्यालय जाने के बाद रात को अपनी जान देने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद की चर्चा, मायके से अकेले लौटना और कमरे का अंदर से बंद मिलना, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बीते 22 अगस्त को दोनों पति-पत्नी अपने-अपने घर गए थे। पति ने पत्नी को उनके मायके में छोड़ा था और खुद अपने घर चले गए थे। रक्षाबंधन के पर्व के बाद 28 अगस्त को परिजनों ने बस से वापस बीपीएससी शिक्षिका को बिहार के लिए रवाना किया था। चर्चा है कि घर जाने और पति के साथ वापस लौटने को लेकर दोनों के बीच कुछ अनबन विवाद भी हुआ था।

बिहार में गुरुजी का डिजिटल वार, सातवें वेतनमान के लिए एक्स पर छिड़ा महा-आंदोलन

पटना, एजेंसी। बिहार के शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान और वित्तीय लाभ की मांग को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर डिजिटल आंदोलन चलाया। शिक्षक संगठनों और बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग के साथ लगातार पोस्ट कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस अभियान में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्षों से जुड़े वेतनमान के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। डिजिटल माध्यम से शुरू किए गए इस आंदोलन में शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वास्तविक वेतन और फिटमेंट का लाभ देने की मांग दोहराई। दिन भर काफी लंबे समय तक यह एक्स पर ट्रेंड में रहा। शिक्षकों का कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बावजूद सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मिलने वाले लाभ और वास्तविक वेतनमान को लेकर अब भी असंतोष है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को एक्स को डिजिटल आंदोलन का मंच बनाया गया। शिक्षकों ने एकजुट होकर हैशटैग के माध्यम से अपनी मांग को सोशल मीडिया पर प्रमुखता से उठाया और सरकार से इस मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की।इस डिजिटल आंदोलन में शिक्षक नेता और बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों को उम्मीद थी कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप वास्तविक वित्तीय लाभ मिलेगा, लेकिन वेतन और फिटमेंट से जुड़े मुद्दों पर शिक्षकों की अपेक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

नेपाल बाढ़ का साइड इफेक्ट,

गंडक नदी में पहुंचीं 90 किलो की रहस्यमयी मछलियां

पश्चिम चंपारण, एजेंसी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। इसके कारण पश्चिम चंपारण और गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी और असामान्य मछलियों के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। गंडक नदी और आसपास के जलस्रोतों में ऐसी मछलियां मिलने के बाद बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मत्स्य विभाग की एडवाइजरी: सरकार के मत्स्य विभाग ने तत्काल एक एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से अनजान या असामान्य दिखने वाली मछलियों को पकड़ने, खरीदने-बेचने और खाने से बचने की अपील की है। विभाग का कहना है कि जब तक किसी मछली की प्रजाति की पहचान और उसके खाने के लिए सुरक्षित होने की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक उसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए।

नेपाल से आया बाढ़ का पानी: बताया जा रहा है कि नेपाल से आया बाढ़ का पानी गंडक नदी में पहुंचने के बाद नदी और उसकी सहायक धाराओं का पानी कई इलाकों में फैल गया है। बाढ़ के दौरान तालाबों, नदियों और दूसरे जलस्रोतों की मछलियां पानी के तेज बहाव के साथ काफी दूर तक बहकर पहुंच सकती हैं। इस दौरान इनके दूषित नालों, मृत जानवरों और अन्य प्रदूषित पदार्थों के संपर्क में आने की आशंका रहती है।

संक्रमण का बढ़ा खतरा: प्रशासन के मुताबिक ऐसी स्थिति में मछलियों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य हानिकारक तत्वों के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं, वाल्मीकिनगर से लेकर धनहा स्थित गौतम बुद्ध सेतु

तक गंडक नदी के किनारे बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ने पहुंच रहे हैं।

90 किलो की विशालकाय मछलियां: इस दौरान मछुआरों के हाथ 10 किलो से लेकर करीब 90 किलो तक वजन वाली बड़ी मछलियां लगने की जानकारी सामने आई है। बड़ी मछलियों के मिलने की खबर फैलने के बाद नदी किनारे लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। इनमें स्थानीय स्तर पर कुछ मछलियों का नाम 'बघार' या 'गोचिटा' बताया जा रहा है।

विशेषज्ञों का अनुमान: वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक समीर कुमार सिन्हा के मुताबिक, 'नेपाल की बाढ़ के बाद गंडक नदी में बहकर पहुंची ज्यादातर बड़ी मछलियों यानी गूंच कैटफिश, होने की आशंका है।' गूंच एक बड़ी मीठे पानी की शिकारी कैटफिश है, जो भारत और नेपाल समेत दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में तेज बहाव वाली नदियों में पाई जाती है।

गूंच कैटफिश की विशेषताएं: गूंच आमतौर पर गहरी नदी, चट्टानों और तेज धार वाले इलाकों में रहती है और छोटी मछलियों, केकड़ों तथा दूसरे जलीय जीवों का शिकार करती है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मछली की पहचान होने मात्र से उसे बाढ़ के दौरान पकड़ी गई मछली के रूप में खाने के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता। खासकर मरी हुई या लंबे समय से बाहर पड़ी मछली तेजी से खराब हो सकती है और उसके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है।

बगहा एसडीएम की अपील: मामले की गंभीरता को देखते हुए बगहा एसडीएम चांदनी कुमारी ने भी लोगों से अपील की है कि नेपाल से बाढ़ के पानी के साथ आई किसी भी अज्ञात अथवा असामान्य मछली को पकड़ने, खरीदने, बेचने या खाने से बचें। यदि किसी मछली की पहचान को लेकर संदेह हो तो संबंधित मत्स्य विभाग से पुष्टि के बाद ही उसके उपयोग पर विचार करें।

प्रशासन की सख्त हिदायत: प्रशासन ने लोगों से यह भी कहा है कि सिर्फ किसी सामान्य रूप से खाई जाने वाली मछली जैसी दिखने के आधार पर किसी अनजान मछली को सुरक्षित न मानें। ऐसी मछली मिलने पर इसकी सूचना जिला मत्स्य पदाधिकारी या स्थानीय प्रशासन को दें।

स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी: वहीं, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी मछली का सेवन कर लिया है और उसके बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है।

अफवाहों से बचने की सलाह: फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और मछली की प्रजाति तथा उसके खाने योग्य होने की आधिकारिक पुष्टि होने तक पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। नेपाल की बाढ़ के बाद गंडक में आई बड़ी और अनजान मछलियों ने जहां लोगों की उत्सुकता बढ़ाई है, वहीं प्रशासन ने इसे लेकर सावधानी बरतने की अपील की है

बिहार की शिक्षा में एआई की एंट्री, मिथिलेश तिवारी ने गूगल फॉर एजुकेशन के साथ की अहम बैठक

पटना, एजेंसी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू करने की तैयारी की है। आने वाले समय में राज्य में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एआई आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। इस दिशा में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गूगल फॉर एजुकेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षकों को एआई और आधुनिक डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने से लेकर चुनिंदा स्कूलों में एआई लैब स्थापित करने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गूगल फॉर एजुकेशन के इंडिया हेड संजय जैन और नीति वर्मा के साथ बैठक कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को तैयार करने पर विचार-विमर्श किया। बैठक में बिहार में गूगल आई एजुकेटर ट्रेनिंग सीरीज को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के स्तर तक विस्तार देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी।

आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण : इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को केवल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ाई में एआई और आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करना है। ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षक यह समझ सकेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीके और विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में कैसे किया जा सकता है।

क्या हुई चर्चा : बैठक में गूगल की ओर से बिहार शिक्षा विभाग को शिक्षकों के लिए निःशुल्क कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत शिक्षकों को एआई आधारित टूल्स और डिजिटल शिक्षा से जुड़े नए संसाधनों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि बदलती तकनीकी दुनिया में छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को भी नई तकनीक के अनुरूप तैयार करना जरूरी है।

प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षकों और विद्यार्थियों को इन टूल्स के निःशुल्क इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोग किया जा सकता है। बिहार में चयनित विद्यालयों में एआई लैब स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया गया। इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक से जुड़े आधुनिक उपकरणों को समझने और उनके शैक्षणिक इस्तेमाल का अवसर मिल सकता है।

अगर पुल होता तो बच सकती थी जानें' नाव हादसे में मां और 12 साल की बच्ची की मौत पर फूटा गुस्सा

सहरसा, एजेंसी। बिहार के सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में तिलावे नदी पार करते समय एक नाव अचानक पलट गई। इस हादसे में एक पैंतीस वर्षीय महिला रूपम कुमारी की डूबने से मौत हो गई है। नाव पर सवार बारह वर्षीय बच्ची नेहा कुमारी नदी की तेज धार में लापता हो गई थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों के बीच मातम पसर गया।

यह दुखद घटना सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के तुर्की स्थित नढ़ेया घाट के समीप मंगलवार शाम करीब छह बजे हुई। तरियामा पंचायत के लगभग बारह से पंद्रह महिला, पुरुष और बच्चे नदी के पार मवेशियों के लिए घास काटने गए थे। शाम को सभी लोग नाव पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया।

प्रत्यक्षदर्शी मिथिलेश यादव के अनुसार नाव जैसे ही घाट के समीप पहुंची, वह अचानक असंतुलित होकर पानी में पलट गई। नाव पलटते ही उस पर सवार सभी लोग गहरे नदी में जा गिरे। इस दौरान कई लोगों ने घास से बंधी रस्सियों का सहारा लिया। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई।

हादसे में कुंदन यादव की पत्नी रूपम कुमारी की जान चली गई। वहीं विष्णुदेव यादव की बारह वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी लापता हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने मंगलवार की रात तक नदी में बच्ची की

काफी तलाश की। सफलता न मिलने पर प्रशासन को सूचित किया गया और स्थानीय स्तर पर राहत कार्य शुरू किया गया।

बुधवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना खोज अभियान तेज किया। करीब 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने लापता नेहा कुमारी का शव नदी से बरामद कर लिया। बच्ची का शव मिलते ही परिजनों और उपस्थित ग्रामीणों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सहरसा सदर अस्पताल भेज दिया गया। प्रशासन मामले की आगे की जांच कर रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय समाजसेवियों में भारी रोष देखा जा रहा है।

भाई ने जहर देकर 4 लोगों को मारा, बहन के लव अफेयर से था नाराज

पटना, एजेंसी। बिहार के पटना बाढ़ में शराब पीने से 4 युवकों की हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर मामले को सुलझा लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ने कबूल किया है कि उसने शराब में जहर मिलाकर 4 युवकों को पिलाई थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया।

क्या था पूरा मामला 30 अगस्त, रविवार की शाम बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में पांच लोग शराब और मछली की पार्टी कर रहे थे। शराब पीते ही 4 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ मिनटों में सभी अचेत होकर गिर पड़े थे। इस बीच शराब पार्टी में शामिल लाली कुमार ने शोर-शराबा कर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सभी को अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ में भर्ती कराया।

हालत इतनी गंभीर थी कि मुंह से झाग निकल रहा था: बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी ने भी नशीले पदार्थ का सेवन करने की बात कही थी। डॉ। श्रेया शेखर के अनुसार सभी की हालत इतनी गंभीर थी कि, उनके मुंह से झाग निकल रहा

था। सभी को बाढ़ से पटना रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गयी।

जहर मिली शराब पीने से हुई थी मौत: पटना ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ में सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर, पटना रेफर कर दिया गया। इस दौरान सभी की मौत हो गई। मृतकों में शशि कुमार (32 वर्ष), विकास राम (40 वर्ष), पंकज सिंह (45 वर्ष) और निशु कुमार (30 वर्ष) शामिल हैं। सभी के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों से अंतिम संस्कार कराकर जांच में जुट गई।

बहन के लव अफेयर से नाराज था भाई: घटना के बाद पुलिस ने एसडीपीओ, बाढ़ 2 के नेतृत्व में 15 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की थी। इस बीच पुलिस को जांच में लव एंगल मिला। एसपी के मुताबिक, लाली कुमार की बहन का मृतक निशु कुमार से अफेयर चल रहा था। इस बात को लेकर लाली के सभी दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। इसके बाद लाली कुमार ने यह कदम उठाया।

वारदात में शामिल 3 गिरफ्तार, एक की तलाश: पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए लाली कुमार और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। जिनमें एक आलू विक्रेता है, जो सब्जी के साथ शराब की भी बिक्री करता था, घटना में शामिल तीसरा आरोपी नाबालिग है, जबकि एक युवक सन्नी कुमार की पुलिस को तलाश है।

अनंत सिंह पहुंचे थे बेढ़ना गांव: इससे पहले जहरीली शराब की बात से नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया था। दूसरी तरफ मंगलवार शाम को मोकामा विधायक अनंत सिंह जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे और हर संभव मदद का भरोसा दिया था।

11 साल में 7 जिलाधिकारी, फिर भी पूरा नहीं हुआ 105 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, अब 8वें से आस

सीतामढ़ी, एजेंसी। बिहार के सीतामढ़ी का ड्रेनेज सिस्टम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हल्की बारिश के बाद तो ड्रेनेज सिस्टम का इतना बुरा हाल हो जाता है कि चारों ओर जलभराव ही नजर आता है। इस जलभराव से जो परेशानी होती है, इसका अंदाजा इसे झेलने वाले लोग ही लगा सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। सीतामढ़ी शहर को जलजमाव की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए वर्ष 2015 में मंजूरी मिली थी। 105 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना 11 साल बाद भी अधूरी है।

जिले की ड्रेनेज सिस्टम बदहाल : सीतामढ़ी शहर के लिए जलजमाव कोई नई समस्या नहीं है। बारिश के मौसम में शहर के कई इलाकों में जलनिकासी बाधित होने के कारण सड़कें और प्रमुख मार्ग पानी में डूब जाते हैं। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए वर्ष 2015 में सरकार ने करीब 105 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी थी।

11 साल से अधूरा काम : योजना का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित नालों का निर्माण कर बारिश के पानी की निकासी को बेहतर बनाना था, ताकि जलजमाव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। योजना की जिम्मेदारी बुडको को दी गई, लेकिन वर्षों गुजरने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान सीतामढ़ी जिले में एक के बाद एक कई जिलाधिकारी आए और उनका तबादला होता रहा। करीब 11 साल के लंबे अंतराल में सात डीएम बदल गए, लेकिन 105 करोड़ रुपये की यह योजना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी है।

बदले 7 डीएम लेकिन नहीं बदली समस्या : इस दौरान जिले में सात जिलाधिकारी आए और उनका तबादला हो गया, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली यह योजना रफ्तार नहीं पकड़ सकी। योजना के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी बुडको को दी गई थी, लेकिन अब तक यह परियोजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है। नए जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने पदभार ग्रहण करते ही योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए शहर का

निरीक्षण किया और बीते दिनों ड्रेनेज सिस्टम के कामों का जायजा लिया।

नए डीएम ने किया निरीक्षण : अब सीतामढ़ी के नए जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने पदभार संभालते ही इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सक्रियता दिखाई है। उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्य की प्रगति, कई स्थानों पर अधूरे पड़े नालों और शहर में जलनिकासी की मौजूदा व्यवस्था को देखा।

उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर इतने वर्षों के बाद भी योजना पूरी क्यों नहीं हो सकी और वर्तमान में इसके तहत कितना काम पूरा हुआ है। नए डीएम के इस निरीक्षण से एक बार फिर शहरवासियों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि वर्षों से अधर में लटकी इस योजना को अब गति मिल सकती है।

स्थानीय लोगों में जगी आस: स्थानीय निवासी संजय राय बताते हैं, कब से सुन रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। अब नए डीएम के पहल से कुछ होगा, अच्छी बात है। इसके बन जाने से लोग जागरुक होंगे और पानी एक जगह जमा होगा। स्वच्छता बनी रहेगी और लोगों को बीमारियां कम होगी।

अधूरे नाले और धीमा निर्माण बना चुनौती : स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना के तहत शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए नालों का निर्माण और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था विकसित की जानी थी। लेकिन कई स्थानों पर काम अधूरा रहने और योजना के अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ने के कारण इसका पूरा लाभ शहरवासियों को नहीं मिल सका।

उठ रहे सवाल : बारिश के दिनों में जब शहर के कई हिस्सों में पानी जमा होता है, तब इस योजना की उपयोगिता और इसके अधूरे रहने का मुद्दा एक बार फिर सामने आ जाता है। स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 105 करोड़ रुपये की योजना पूरी होने में इतनी लंबी देरी क्यों हुई

हर बारिश में नारकीय स्थिति : सीतामढ़ी शहर में जलजमाव की समस्या बारिश के साथ और गंभीर हो जाती है। मुख्य सड़कों से लेकर कई मोहल्लों तक पानी जमा होने से लोगों को परेशानी होती है। व्यवसायियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है और राहगीरों को जलजमाव से होकर गुजरना पड़ता है।

शहरवासियों का कहना है कि जब सरकार ने 11 साल पहले जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए इतनी बड़ी राशि की योजना बनाई थी, तो अब तक इसका पूरा नहीं होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। लोगों को उम्मीद थी कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम तैयार होने के बाद शहर की जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन वर्षों बाद भी स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया।

नए डीएम के सामने बड़ी चुनौती: तनय सुल्तानिया के सामने अब इस योजना को धरातल पर उतारने की बड़ी चुनौती है। पदभार संभालने के तुरंत बाद योजना का निरीक्षण करना यह संकेत देता है कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है।

संक्षिप्त समाचार

रंगों के साथ शुरू हुआ विद्यार्थियों का रचनात्मक सफर

लखनऊ, एजेंसी। रंगों, रेखाओं और नई कल्पनाओं के बीच डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के वास्तुकला व योजना संकाय में दो दिवसीय नवागमन ओरिएंटेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कला कार्यशाला में प्रथम वर्ष के नए विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने अलग-अलग कला माध्यमों से अपनी रचनात्मकता को कैनवास पर उतारा। विद्यार्थियों ने कैनवास हैंड बैग पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग और जलरंग चित्रण सीखा। कोलकाता के चित्रकार सौरभ शी ने जलरंग की बारीकियां बताईं। उन्होंने रंगों, प्रकाश और छाया के प्रयोग के साथ ब्रश चलाने की तकनीक सिखाई। कार्यक्रम संयोजक भूपेंद्र कुमार अस्थाना व समन्वयक आर्किटेक्ट ताबिश अहमद अब्दुल्ला रहे। कलाकार धीरज यादव व रत्नप्रिया ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। समापन पर संकाय की अधिष्ठाता डॉ. वंदना सहगल ने विद्यार्थियों की कलाकृतियों की सराहना की।

पाचन तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है आंतों का स्वास्थ्य

लखनऊ, एजेंसी। ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मंगलवार को किया। कुलपति अजय तनेजा और डीन तल्हीर फात्मा के निर्देशन में यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसकी थीम पोषण की शक्ति को जानें है, जिसका उद्देश्य पोषण, स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के पहले दिन गृह विज्ञान विभाग में आयोजित व्याख्यान में क्लीनिकल आहार विशेषज्ञ अमरीन कुरैशी ने बताया कि आंतों का स्वास्थ्य पाचन तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कुरैशी ने रेशेदार, प्राकृतिक आहार और पर्याप्त पानी पीने की अपील की। संतुलित भोजन स्वस्थ शरीर और सक्रिय मस्तिष्क की बुनियाद है। नेहा मोहन सिन्हा ने जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी।भोजन में विविधता, संतुलन, स्वच्छता और उचित मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। कीर्तिमा सचान, कल्पना देवी और अंजलि सिंह का योगदान रहा।

बनारस कोचिंग डिपो पहुंचे डीआरएम ने परखी उपकरणों की गुणवत्ता

वाराणसी, एजेंसी। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आशीष जैन ने मंगलवार को बनारस रेलवे स्टेशन के पास कोचिंग डिपो में सुरक्षा उपकरणों की जांच कर उसकी गुणवत्ता, कार्य करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों से डिपो में कोच की सफाई के साथ ही अन्य मेंटेनेंस संबंधी कामकाज की नियमित मॉनीटरिंग करते रहने को कहा। डीआरएम ने कोच में लगे फायर स्मोक एवं डिटेक्शन सिस्टम की जांच की। उन्होंने देखा कि धुआं या आग लगने की स्थिति में यह सिस्टम किस प्रकार अलर्ट देता है और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ही सिस्टम के बैटरी बैकअप, अलर्ट मिलने के बाद कोच में ब्रेक लगने, सिस्टम को रीसेट करने, जरूरत पड़ने पर इसे बंद करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। उनके साथ वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अभिषेक राय भी मौजूद रहे।

तीज के रंग में रंगीं महिलाएं, कजरी लोकनृत्य पर झूमीं

वाराणसी, एजेंसी। केंद्रीय ब्राह्मण सभा (महिला मंच) की ओर से तीज मिलन समारोह का आयोजन मंगलवार को महमूरगंज स्थित होटल में हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. मल्लिका तिवारी और विशिष्ट अतिथि बिपाशा गोस्वामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था की राष्ट्रीय महासचिव वंदना झा और संयोजिका जमुना शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर पांच महिलाओं चिकित्सक डॉ. श्वेता मिश्रा, एथलीट सुधा रानी, साहित्यकार डॉ मंजरी पांडेय, बबिता पांडेय (उद्योग) और पुष्पा बनर्जी को क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। श्वेता अग्निहोत्री ने प्रश्नोत्तरी करवाई। प्रीती, रंजन और श्वेता ने सामूहिक कजरी गायन किया। रेनू मिश्रा ने तीज पर कविता पाठ किया जबकि रेखा अग्निहोत्री और मंजू मिश्रा ने लोकनृत्य प्रस्तुत किया। डॉ. संध्या ओझा ने तीज के महत्व पर प्रकाश डाला। संचालन आनंदिता तिवारी ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीणा अग्निहोत्री ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस मौके पर धाविका नीलू मिश्रा, संगीता मिश्रा, पूर्णिमा अवस्थी आदि मौजूद रहीं।

हाईटेक होगा कंट्रोल रूम, एंबुलेंस के लिए बनेगा ग्रीन कॉरिडोर

आगरा, एजेंसी। श्रीरामलीला महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जनकपुरी में एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपात स्थिति में एंबुलेंस के निर्बाध आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष व विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की मौजूदगी व जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए गए। जिलाधिकारी ने जनकपुरी में एक एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा जिसमें नगर निगम, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, टोरेंट और अग्निशमन सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी तैनात रहेंगे। महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक-चौबंद रखने के लिए चिकित्सकों की टीम और एंबुलेंस तैनात रहेंगी। इसके अलावा लटकते बिजली-इंटरनेट के तारों को हटाने, सड़कों के गड्ढे भरने, जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और प्रतिदिन एंटी-लार्वा का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य, डीएफओ राजेश कुमार, प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत व अन्य मौजूद रहे। पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 25 सितंबर को मुकुट पूजन से होगा। 6 अक्टूबर को प्रभु श्रीराम की भव्य बरात निकाली जाएगी जिसमें 200 से अधिक झांकियां, अखाड़े और बैंड शामिल होंगे। इस बार गोवर्धन महाराज की विशेष झांकी और सामाजिक सरोकारों का संदेश प्रमुख आकर्षण रहेगा।

सितंबर के दूसरे ही दिन प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश

लखनऊ, एजेंसी। अगस्त में हुई जोरदार बारिश ने उत्तर प्रदेश में कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में साल 2018 के बाद यह 21वीं सदी का सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त रहा। पूरे प्रदेश में सामान्य 235.5 मिमी के मुकाबले 291.3 मिमी बारिश हुई। प्रयागराज में अगस्त के दौरान 631.6 मिमी और बांदा में 646 मिमी बारिश दर्ज हुई। इन दोनों जिलों में वर्ष 1901 से अब तक अगस्त में इतनी बारिश कभी दर्ज नहीं की गई।

बंगाल की खाड़ी के सात सिस्टम बने बारिश की बड़ी वजह : क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सात निम्न दबाव क्षेत्रों ने अगस्त में मानसून को लगातार सक्रिय रखा। प्रदेश में अगस्त के दौरान सामान्य 235.5 मिमी के मुकाबले 291.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे पहले वर्ष 2018 में अगस्त में 293.1 मिमी बारिश हुई थी।

इधर, मंगलवार को दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक 147 मिमी और सोनभद्र में 140 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए यूपी के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले तीन से चार दिन दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्यांचल में बारिश की रफ्तार धीरे-धीरे कम होने लगेगी।

सितंबर में पश्चिम में कम, दक्षिण-पूर्व में ज्यादा बारिश के आसार : सितंबर के मासिक पूर्वानुमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक, जबकि मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकती है। हालांकि, सितंबर में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

इन जिलों में है भारी बारिश का येलो अलर्ट : बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।

यहां है गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका : सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालोन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।

राजधानी में सितंबर की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ हुई। मंगलवार को सुबह से ही शहर के ज्यादातर इलाकों में घने काले बादल छाए रहे। सुबह करीब नौ बजे बारिश शुरू हुई, जो 11 बजे तक चलती रही। इससे दफ्तर और अन्य कामों से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दोपहर बाद एक बार फिर बादल सक्रिय हुए और तेज बारिश शुरू हो गई। देर शाम करीब दो घंटे तक हुई जोरदार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा।रिमझिम बारिश का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शाम तक लखनऊ के चिनहट में 59 मिमी, 1090 चौराहे पर 54 मिमी और राजभवन क्षेत्र में 45.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक महसूस की गई।

अगस्त में सामान्य से 64 फीसदी अधिक हुई बारिश : इधर मौसम विभाग ने लखनऊ में अगस्त में हुई बारिश के आंकड़े भी जारी किए हैं। इसके अनुसार लखनऊ में अगस्त के दौरान 330.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 64 फीसदी अधिक है। अगस्त में शहर में सामान्य बारिश 202 मिमी मानी जाती है। इसके पहले साल 2024 में अगस्त माह में 338.7 मिमी और साल 2018 में 405.5 मिमी बारिश रिकार्ड की गई थी।

एक ही पौधे में बैंगन और टमाटर, छिक्कल समेत खाइए हरी मटर

लखनऊ, एजेंसी। जनभवन (राजभवन) में लगी फल, शाक-भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन शनिवार को दर्शकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। यहां लगे कई स्टॉलों पर रखे उत्पादों, सब्जियों और फूलों ने उनकी विशेषता की वजह से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी का स्टॉल इस बात के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा क्योंकि यहां एक ही पौधे में बैंगन और टमाटर साथ-साथ उगे हुए थे। इसे देखने और छूने के लिए लोग बेताब दिखे। इसी स्टॉल पर हरी मटर की एक किस्म ने भी लोगों को खूब लुभाया जो छिक्कल समेत खाई जाती है। इसका स्वाद भी लाजवाब था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया।

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के स्टॉल पर मौजूद रोग विशेषज्ञ डॉ. सुदर्शन मौर्य ने बताया कि ग्राफटिंग के जरिये एक ही पौधे में बैंगन और टमाटर को साथ-साथ उगाया गया है जिसका स्वाद भी लाजवाब है।

संस्थान की ओर से इसे नाम दिया गया है ब्रिमेटो। इसके अलावा काशी तृप्ति नाम की हरी मटर की खासियत है कि इसके छिक्कल समेत खाया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बनने वाले मिडडे मील में इसका प्रयोग आदर्श माना जा रहा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है जो बच्चों के विकास के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा यहां मौजूद विशेष प्रजाति के काशी चेरी टमाटर का साइज बेर के बराबर होता है लेकिन स्वाद बेमिसाल होता है।

छाया रहा बिजली और सड़क का मुद्दा, सत्ता पक्ष के सदस्य भी हमलावर

गोरखपुर , एजेंसी। लंबे अरसे बाद जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य भी बिजली और सड़क जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर दिखे। मुख्य विकास अधिकारी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। इसके बाद डीडीयू बैठक में शामिल हुए।

बैठक में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सीडीओ या उनके प्रतिनिधि अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य है लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद अध्यक्ष साधना सिंह ने डीएम को फोन किया। इसके बाद डीएम ने कैंपियरगंज में समाधान दिवस पर गए डीडीओ को तुरतं जिला पंचायत पहुंचने का निर्देश दिया। उसके बाद डीडीओ बैठक में पहुंचे। इसके बाद बैठक शुरू हुई तो भाजपा जिपंस मायाशंकर शुक्ल ने बिजली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। उनके क्षेत्र बड़हलगंज और गगहा ब्लॉक के कई गांवों में तीन-तीन साल से पोल टूटे हुए हैं। कई बार कहने के बाद भी वह बदले नहीं गए। खखाइजखोर गांव में एक सब स्टेशन बना है लेकिन वह अब तक चालू नही हो पाया। वहां बना भवन सात साल में ही जर्जर हो गया।

पिपराइच व भटहट क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र के अनेक गांव में आज भी बांस-बल्ली के सहारे लोगों के घरों तक बिजली पहुंच रही है। इसे लेकर उन्होंने एक्सईएन को अपने क्षेत्र में उन गांवों का भ्रमण भी कराया था। सदन में उपस्थित बिजली विभाग के एसडीओ ने कहा कि बहुत जल्द खंभे की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुड़िला-सोहसा-बनचरा रोड के किनारे रहने वाले लोगों को जल निकासी की समस्या है। उसका समाधान कराना आवश्यक है। कौड़ीराम ब्लाक के जिला पंचायत सदस्य मनोज शुक्ल ने भिटहा गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र के भवन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भवन आठ साल पहले बना था लेकिन अब वह जर्जर हो गया है। पिलर का सरिया स्पष्ट दिख रहा है। वह भवन टूटने के कगार पर है। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मझगांवा में शहीद साहब शुक्ला के नाम पर एक इंटर कॉलेज बना है लेकिन वहां जाने का रास्ता ही नहीं है।

जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। सदस्यों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनकी भावनाओं का आदर होगा। बैठक में जिला पंचायत सदस्य राम प्रताप यादव, दिलीप सिंह, रवि प्रकाश निषाद, सुनील गुप्ता आदि ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा।

वायरल, डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से सहमे लोग, स्वाइन फ्लू का डर; इन लक्षणों पर हो जाएं अलर्ट

आगरा, एजेंसी। मौसम में बदलाव के साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया के मामले मिल रहे हैं। राहत की बात यह है कि शहर में अभी तक स्वाइन फ्लू का एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए लगातार संदिग्ध मरीजों की जांच करा रहा है।अस्पतालों में मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंगलवार को ओपीडी में लगभग 3,922 मरीज कराने पहुंचे। इनमें 1,337 नए मरीज दर्ज किए गए, जबकि 2,585 पुराने मरीज फॉलो-अप और परामर्श के लिए पहुंचे थे। ओपीडी में सबसे ज्यादा संख्या खांसी, जुकाम, गले दर्द की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की रही।

स्वाइन फ्लू पर सतर्कता, घबराने की जरूरत नहीं : एसएन मेडिकल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि शहर में फिलहाल स्वाइन फ्लू का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके बावजूद विभाग पूरी तरह सतर्क है और लगातार सैंपलिंग व कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। इससे घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, तुरंत लें डॉक्टरी सलाह : डॉ. मनीष ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को एक हफ्ते से अधिक समय तक लगातार खांसी रहे, गले में खराश हो, गला खराब हो या बोलने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो इसे सामान्य मानकर अनदेखा न करें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क कर अपनी जरूरी जांच कराएं।

अफ्रीकी देशों से आने वालों की जांच की जाएगी : मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध मरीज मिलने पर कंट्रोल रूम के 9458569043 और 0562-260412 (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) पर जानकारी दे सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

- खान-पान में ठंडी चीजों, आइसक्रीम या फ्रिज के पानी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें।

- पीने के लिए सादे या हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें।

- बुखार या खांसी लंबे समय तक टिकने पर बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवाएं न लें।

मऊ में कक्षा एक की छात्रा सामरा ने लगाई डीएम से सड़क मरम्मत की गुहार, कुछ ही घंटों में काम शुरू

वाराणसी, एजेंसी। वार्ड 17 निवासी कक्षा एक की छात्रा सामरा नाज (7) के घर के पास की सड़क का जल्द निर्माण शुरू होगा। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के निर्देश पर मंगलवार को नगर पालिका की टीम ने भूमि की पैमाइश की। सड़क निर्माण के लिए एस्टीमेट भी तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में सोमवार को जनसुनवाई में पिता के साथ पहुंची सामरा नाज ने डीएम आनंद वर्धन से खराब सड़क की समस्या बताई थी। कहा था, रास्ता खराब होने के कारण स्कूल जाते समय उसे आने-जाने में परेशानी होती है। कई बार चोट भी लग जाती है। स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जिसके चलते स्कूल में डांट सुननी पड़ती है।

जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने बताया कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। बच्चों और आम नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कहीं डॉक्टर है तो अल्ट्रासाउंड नहीं, कहीं एक्सरे है तो डॉक्टर नहीं

अलीगढ़ , एजेंसी। लखनऊ तक जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहां के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ऐसी है कि मरीज हाजिर हैं, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं। कहीं प्रसव के लिए डॉक्टर है तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं, कहीं एक्सरे मशीन है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। खैर तहसील में ऑक्सीजन संयंत्र ही चार साल से बंद पड़ा है। अतरौली के बाद जिले की अन्य तहसीलों में भी दावों और हकीकत के बीच अंतर सामने लाती यह रिपोर्ट।

इगलास : बाहर से कराओ अल्ट्रासाउंड, फिर करेंगे प्रसूति : इगलास की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का भरोसा तोड़ रही हैं। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रसूति के लिए डॉक्टर है, लेकिन बिना अल्ट्रासाउंड गर्भ में भ्रूण की स्थिति का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पहले बाहर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है, फिर प्रसूति पर डॉक्टर निर्णय ले रहे हैं। मंगलवार को हरौंथा निवासी विमलेश देवी अपनी बहू मीना को लेकर यहां पहुंचीं। पांच माह की गर्भवती मीना को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर जाना पड़ा। घर में किसी दूसरे बच्चे को खिलाते समय उसके पेट पर बच्चे ने लात मार दी जिसके बाद मीना को पीड़ा शुरू हुई। परिजन पहले हाथरस के प्राइवेट अस्पताल और फिर उन्हें आनन फानन में सीएचसी लाना पड़ा। यहां आकर डॉक्टर ने मीना की पूरी कहानी सुनी और सही फैसला लेने के लिए बाहर जाकर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जिसमें समय और रुपये दोनों खर्च हुए। इसी तरह यहां एक्सरे की सुविधा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट देखने वाला हड्डीरोग विशेषज्ञ नहीं है। नाक, कान और गला में तकलीफ होने पर मरीजों को सीधे अलीगढ़ जाकर इलाज कराने की नसीहत मिल रही है।

- सीएचसी में एक्सरे की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने से बाहर जाना पड़ता है। यहां ऑर्थोपेडिक और ईएनटी विशेषज्ञ की तैनाती होनी चाहिए। - गेंदा सिंह निवासी चिरौली

- डॉक्टरों की कमी के बारे में विभान को जानकारी है। अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब तक हमारे पास मशीन नहीं आई है।

खैर : तीन दिन होंगे एक्सरे, बाकी दिन की गारंटी नहीं : खैर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थिति ऐसी है कि वहां एक्सरे के लिए केवल एक तकनीशियन है। इनकी तीन दिन खैर और बाकी दिन टप्पल सीएचसी में ड्यूटी रहती है। जब तकनीशियन नहीं रहते तो उनकी गैर हाजिरी में एक्सरे बाहर से प्राइवेट केंद्रों पर करवाना पड़ता है। इगलास की तरह यहां भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है जबकि डॉक्टर हाजिर है। कोरोना के समय 2021 में 30 लाख रुपये के खर्च से सरकार ने यहां ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की ताकि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन कुछ ही समय बाद यह बंद हो गया जिसका कारण सीएचसी पर मौजूद कर्मचारियों को भी सही से स्पष्ट नहीं है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की नियमित तैनाती नहीं है जिससे आपात स्थिति में विशेषज्ञ उपलब्ध न होने पर गर्भवती महिलाओं को अलीगढ़ रेफर करना पड़ रहा है। .

मुझे यहां आकर हर बार बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी गई। जब भी पूछो तो कहते हैं कि शिविर में आ जाना, तब फ्री करवा देंगे। - शशि, निवासी अंडला

. पैर में चोट लगने के बाद यहां आया था, लेकिन एक्स-रे करने वाला ही नहीं था जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। प्राइवेट में नहीं करा सकता, इसलिए जब टेक्नीशियन आएगा तभी एक्स-रे के लिए आउंगा। -रामवीर निवासी अंडला

.एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियमित व्यवस्था और अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने के लिए विभाग को जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इन सुविधाओं की पूर्ति नहीं हुई। आपातकालीन प्रसव के लिए अलीगढ़ रेफर कर रहे हैं।

गभाना : एक्सरे खराब, लैब टेक्नीशियन भी नहीं, 66प्रतिशत नर्सिंग पद भी खाली : गभाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक्सरे मशीन खराब होने से मरीजों को बाहर निजी केंद्रों पर एक्सरे कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेबर रूम के बाहर लगा पंखा भी खराब पड़ा है। यहां बाल रोग विशेषज्ञ, बेहोशी विशेषज्ञ और सर्जन की कमी है। वर्तमान में अधीक्षक समेत केवल चार चिकित्सक ही मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इसी तरह 12 पद स्वीकृत होने के बावजूद यहां चार नर्स तैनात हैं। लैब टेक्नीशियन भी नहीं है। अस्पताल परिसर में जगह-जगह घास उगी हुई है और बारिश का पानी भरा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है।

- एक्सरे मशीन खराब है, मजबूरी में बाहर से एक्सरा करना पड़ रहा है। सीएचसी पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। - राधेश्याम

- खांसी-सर्दी के चलते मुझे यहां आना पड़ा, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी सिरप नहीं मिला। - रामबती

संक्षिप्त समाचार

अब पूर्वी दिल्ली के थाने में दिव्यांगों को मिलेगा खास इंतजाम, तैनात किए जाएंगे नोडल अधिकारी

नईदिल्ली, एजेंसी। जिले के सभी पुलिस थानों में अब दिव्यांगजनों को सुगम सहायता प्रदान करने और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समर्पित नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ की निरंतर पहल के बाद पुलिस प्रशासन ने इस जनहितकारी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजीव कुमार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले के प्रत्येक थाने में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) या उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये अधिकारी दिव्यांगजनों को थाने में प्रवेश से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक हर संभव सहायता देंगे। साथ ही उनकी समस्याओं पर समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संवेदनशीलता और सख्त कानूनी अनुपालन पर जोर पुलिस प्रशासन ने सभी थानों के कर्मियों को दिव्यांगजनों के साथ अत्यधिक संवेदनशील, सम्मानजनक और सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सभी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। बीट स्टाफ और गश्त करने वाले पुलिस बलों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांग नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। सम्मान और अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम दिल्ली भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक अरुण राय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उनका प्रकोष्ठ दिव्यांग समाज की मांगों और समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाता रहा है। पूर्वी जिला पुलिस की यह पहल दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय और मील का पत्थर साबित होगी।

जेब में वोटर कार्ड है, फिर भी नहीं डाल पाएंगे वोट! दिल्ली सीईओ की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि आपकी जेब या अलमारी में चुनाव आयोग का बना मतदाता पहचान पत्र सुरक्षित है और आप आने वाले चुनाव में आसानी से वोट डाल लेंगे तो आप भ्रम में हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल मतदाता पहचान पत्र हाथ में होना आपको मतदान का अधिकार नहीं देता है। 31 अगस्त, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के संदर्भ में जारी अपनी विशेष अपील में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोल्ड अक्षरों में स्पष्ट किया है, 'यह फिर बताया जा रहा है कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) रखना किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का हकदार नहीं बनाता है। व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। 30 जून से 17 अगस्त, 2026 के बीच चले गणना (एन्युमरेशन) चरण के दौरान जिन लोगों के गणना फार्म जमा नहीं हो पाए हैं या जो सत्यापन के दौरान घर पर नहीं मिले, उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे लोगों के पास भले ही वर्षों पुराना या नया वोटर कार्ड हो, लेकिन अगर 31 अगस्त को जारी सूची में उनका नाम कट चुका है, तो वे मतदान केंद्र पर कार्ड दिखाकर भी वोट नहीं डाल सकेंगे।

दिल्ली से मथुरा और वाराणसी के लिए चलेंगी जन्माष्टमी स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली, एजेंसी। जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा और अन्य धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। इससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दिल्ली से मथुरा, रींगस और वाराणसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। मथुरा और रींगस जन्माष्टमी विशेष ट्रेनों में सिर्फ अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। हजरत निजामुद्दीन-मथुरा (04410/04409)- तीन, चार और पांच सितंबर को यह विशेष अनारक्षित ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से पूर्वाह्न 10.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1.05 बजे मथुरा पहुंचेगी। वापसी में मथुरा से दोपहर 1.35 बजे चलकर शाम पौने पांच बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।

भारत में बढ़ रहा फैटी लिवर का खतरा, 38.6% वयस्क और 35.4% बच्चे प्रभावित; कम उम्र में आंत का कैंसर भी चिंता

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में पेट और लिवर से जुड़ी बीमारियों का प्रभाव तेजी से बदल रहा है। संक्रामक बीमारियों का असर कम होने के साथ अब कम उम्र में बढ़ रहा आंत का कैंसर, मल में खून या पेट की परेशानी को नजरअंदाज करना इसे बढ़ावा दे रहा है।

इसके साथ मोटापा, मधुमेह और खराब जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां भी बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 38.6 प्रतिशत वयस्क और 35.4 प्रतिशत बच्चे फैटी लिवर से प्रभावित हैं।

चिंता की बात यह है कि शुरुआत में इसके स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते और बीमारी बढ़ने पर लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है।

देश में पहली बार होने जा रही विश्व गैस्ट्रोएंटरोलाजी कांग्रेस 2026 से पहले मंगलवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलाजी एवं ह्यूमन न्यूट्रिशन विभागाध्यक्ष और भारतीय आहूजा ने पाचन तंत्र और लिवर से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती चुनौती पर जानकारी

गैस्ट्रोएंटरोलाजी सोसायटी के अध्यक्ष प्रो. डा. प्रमोद गर्ग, प्रो. डा. गोविंद मखारिया, प्रो. डा. शालिमार और प्रो. डा. विनीत साझा की। डा. प्रमोद गर्ग ने बताया कि देश बीमारियों के बदलते दौर से गुजर रहा है। रोकथाम योग्य बीमारियों पर नियंत्रण के बाद मेटाबोलिक बीमारियां बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं।

फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जिसे समय रहते जांच के जरिये पहचाना जा सकता है। एक प्रश्न के उत्तर में डा. शालिमार ने बताया कि फैटी लिवर का मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और शरीर में बढ़ी हुई चर्बी से गहरा संबंध है।

डा. विनीत आहूजा ने कहा कि एंडोस्कोपी, एआइ और माइक्रोबायोम अनुसंधान से बीमारी की पहचान और इलाज में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं।

कम उम्र में भी बढ़ रहा आंत का कैंसर

विशेषज्ञों ने कोलोरेक्टल यानी बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर को भी बढ़ती चिंता बताया। इसके मामले अब कम उम्र के युवाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। वर्ष 2022 में भारत में पुरुषों में 40 हजार 430 और महिलाओं में 24 हजार 433 नए मामले सामने आए।

80 लाख के लालच में मौसी को मेले भेजा और घर में भेजे हत्यारे, रोहिणी हत्याकांड में प्रेमी संग साली की बेटी समेत 4 गिरफ्तार

नईदिल्ली, एजेंसी। रोहिणी सेक्टर-3 में मंगलवार रात 60 वर्षीय राकेश खन्ना की हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह घर में अकेले थे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मृतक की साली की बेटी सिमरन और उसके प्रेमी हिमांशु के साथ पारस और चिराग को गिरफ्तार कर लिया। जांच और पूछताछ में पता चला है कि वे बुजुर्ग द्वारा कुछ समय बेचे गए फ्लैट की मोटी रकम को हड़पने की फिराक में थे। यह रकम करीब 80 लाख बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग को अकेला देखकर आरोपितों ने लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी आरोपितों से पूछताछ कर रही है और हत्या की पूरी वजह की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय राकेश की पत्नी बाजार गई हुई थीं। इसी दौरान कुछ लोग घर में पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, राकेश खन्ना की हत्या की साजिश सिमरन ने अपने प्रेमी हिमांशु के साथ मिलकर रची थी। हिमांशु जिम चलाता है। साजिश के तहत सिमरन ने पहले अपनी मौसी को कुछ रिश्तेदारों के साथ मेला देखने के लिए भेज दिया, ताकि वारदात के समय घर पर कोई मौजूद न रहे। इसके बाद

दिल्ली में डेंगू-मलेरिया का बढ़ा प्रकोप, एमसीडी की फॉगिंग पर पार्षदों ने उठाए सवाल; बोले- मशीनें खराब

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है डेंगू के जहां 311, मलेरिया के 119 और चिकनगुनिया के 22 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है लेकिन एमसीडी जमीनी स्तर पर

कोई कार्य नहीं कर रही है। न तो फागिंग हो रही है न ही दवाओं का छिड़काव हो रहा है। इससे मरीजों की संख्या और बढ़ने का अनुमान हैं। एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में स्वयं भाजपा के ही पार्षदों ने यह मुद्दा उठाया। हेमचंद गोयल द्वारा लगाए गए अल्पकालिक चर्चा पर यह बात सामने आई। हेमचंद गोयल ने कहा कि न तो फागिंग हो रही है और बड़ी गाड़ियों पर इलाके में फागिंग की जाती थी वह भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। इससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दवाइंया तक नीचले स्टाफ के पास नहीं है। हालांकि निगम स्वास्थ्य अधिकारी-2 अशोक रावत ने जमीनी स्तर पर कार्य करने की बात कही जिसे एक सिरे से स्थायी समिति के ज्यादातर पार्षदों ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने बोला की हर वार्ड में तीन से चार मशीनें फागिंग की दे रखी है। जिस पर स्थायी समिति के सभी पार्षदों ने इसे खारिज कर दिया। पार्षदों ने यह भी कहा कि यह मशीनें खराब है चलती तक नहीं है। साथ ही जो मशीनें हैं उनके चलाने के लिए कर्मचारी तक नहीं है। जो मौजूदा डीबीसी कर्मी है वह यह मशीनें चलाने के लिए मना करते हैं। स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन सत्यपाल सिंह ने कहा कि स्थिति बहुत खराब है। मच्छरजनित बीमारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कहते हैं उनके पास दवाइयां नहीं है। क्योंकि जब भी जोनल अधिकारियों से बात कही जाती है तो वहीं कहते हैं कि दवा की कमी है। नेता सदन जयभगवान यादव ने कहा कि डीबीसी कर्मचारी क्योंकि अब एमटीएस हो गए हैं तो उन्हें भी यह मशीनें चलानी पड़ेगी इसके लिए उन्होंने सर्कुलर निकालने की बात कही।

अशोक रावत के दावों पर स्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि जो बाते अधिकारियों की ओर से कही जा रही है वह पार्षदों के अनुसार सही साबित नहीं होती है। इसलिए अधिकारी इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखित में दें। उल्लेखनीय है कि एमसीडी की रिपोर्ट के अनुसार वहीं, शशि यादव ने अस्पतालों में एच1 एन1 की कोई तैयारी न होने की भी बात कही। साथ ही सवाल उठाया कि निगम के अस्पतालों में इसके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। दिल्ली में बेसहारा गायों से होने वाली परेशानी का मुद्दा स्थायी समिति की बैठक में उठा। दैनिक द्वारा वसंत कुंज में बेहसहारा गायों की समस्या को लेकर उठाई गई खबर का जिक्र स्थायी समिति में भाजपा पार्षद जगमोहन मेहलावत ने किया। उन्होंने कहा कि दैनिक ने इस समस्या को उठाया है। ऐसे में हमें चिंता करनी चाहिए कि बेसहारा गायों को गोशाला में भेजा जाए।

अब धरातल पर उतरेगा दिल्ली के विकास का रोडमैप, एमपीडी-2047 के लिए डीडीए का तीन माह का आउटरीच प्लान तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली का मास्टर प्लान (एमपीडी) 2047 की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं लोकनिवास का फोकस इसके क्रियान्वयन पर है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण इस कार्य में आने वाली बहु निकाय व्यवस्था की मुख्य अड़चन को भी दूर किया जा रहा है। एलजी एवं डीडीए के अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू का स्पष्ट निर्देश है कि दिल्ली सरकार, एमसीडी, जल बोर्ड एवं डीडीए जैसे कुछ निकाय आपस में मिलकर कार्य करेंगे जबकि कुछ कार्य पूरी तरह से अलग अलग निकाय को सौंप दिया गया है। मसलन, ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को डीडीए ही संभालेगा जबकि पीएम उदय योजना केवल एमसीडी के पास ही रहेगी। मंगलवार शाम लोकनिवास में चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में एलजी और डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवन कुमार ने इसे लेकर विस्तृत रूप से बातचीत की। डीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि मास्टर प्लान 2047 को धरातल पर उतारने के लिए एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना भी बनाई है। इसके तहत डीडीए अगले तीन माह के भीतर

हितधारकों के साथ 20 से अधिक बैठकें आयोजित करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सांसदों, विधायकों, सरकारी एजेंसियों, पेशेवर संस्थाओं, उद्योग जगत, निवासियों और भूस्वामियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर बेहतर तालमेल बिठाना और नई योजनाओं के प्रविधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजधानी में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुलभ बनाने के लिए सीआइआइ, फिक्की, पीएचडीसीआई, एसोचैम और डीएसआइआइडीसी जैसे प्रमुख उद्योग निकायों के साथ चर्चा की जाएगी। वहीं, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), हाइ-डेंसिटी कॉरिडोर (एचडीसी), लैंड पूलिंग और लो-डेंसिटी एरिया (एलडीए) जैसे अवसरों पर मंथन के लिए आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर और निजी डेवलपर को जोड़ा जाएगा। साथ ही, जमीनी स्तर पर ग्रुप हाउसिंग के पुनर्विकास के लिए आरडब्ल्यूए और सहकारी समितियों के साथ संवाद साधा जाएगा। इस तीन महीने के आउटरीच कार्यक्रम में कम सघन क्षेत्रों, यमुना के कायाकल्प और दिल्ली के ब्लू-ग्रीन नेटवर्क का विकास, विरासत संरक्षण, व्यावसायिक केंद्रों का विकास और पुनर्विकास, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, भीड़भाड़ कम करने और गतिशीलता में सुधार के उपायों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और अन्य संबंधित हितधारकों की भागीदारी के साथ दिल्ली के शिक्षा और चिकित्सा केंद्रों के विकास पर हितधारकों के साथ बातचीत करने का भी प्रस्ताव है।

ट्रंप ने अपने करीबी अधिकारी को दी बड़ी जिम्मेदारी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे कार्यकारी नौसेना सचिव हंग काओ को स्थायी नौकरी के लिए नामांकित कर रहे हैं। ट्रंप ने नौसेना के पूर्व अधिकारी को ऐस समय नियुक्ति दी है, जब ऐसी चिंताएं सामने आई हैं कि ईरान युद्ध के दौरान कुछ नाविकों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। दरअसल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को करीब नौ महीने समुद्र में बिना रुके तैनात रहना पड़ा, जिससे कई अमेरिकी नौसैनिकों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। अप्रैल के आखिर में जॉन फेलन के अचानक और बिना किसी कारण के नौकरी छोड़ने के बाद हंग काओ को नौसेना का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया था। जॉन फेलन ने कभी नौसेना में सेवाएं नहीं दी थीं या सर्विस में कोई सिविलियन लीडरशिप रोल भी नहीं निभाया था। वहीं काओ ने नेवी में स्पेशल ऑपरेशन्स ऑफिसर के तौर पर 25 साल बिताए और इराक और अफगानिस्तान में स्थ्रुटीमों और स्पेशल फोर्सेज के साथ काम किया। ट्रंप ने काओ की नियुक्ति का एलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे एक सच्चे योद्धा को नॉमिनेट करते हुए खुशी हो रही है।' उन्होंने सीनेट से अपील करते हुए कहा कि इस योद्धा को जल्द से जल्द कन्फर्म करें। काओ ने सोशल मीडिया पर इसे नेवी और मरीन कॉर्प्स टीम के महान योद्धाओं का नेतृत्व करना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। काओ का नामांकन ऐसे समय में हुआ है जब कुछ लोग, जिनमें कांग्रेस में डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं। मानते हैं कि ट्रंप नेवी पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं।

पश्चिम एशिया में चीन बढ़ा रहा दखलः मिस्र पहुंचे शी जिनपिंग, अमेरिका के करीबी देश में बीजिंग की बढ़ रही पकड़

काहिरा, एजेंसी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह मिस्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। यह यात्रा चीन और मिस्र के बीच आर्थिक एवं राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की सामान्य कवायद नजर आती है, लेकिन इसके पीछे पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव की बड़ी रणनीति भी देखी जा रही है।

अमेरिका के प्रमुख वैश्विक प्रतिद्वंद्वी चीन के लिए मिस्र पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का अहम केंद्र बनता जा रहा है। वहीं, मिस्र अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। ऐसे में शी की काहिरा यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों से आगे क्षेत्रीय भू-राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शी जिनपिंग मंगलवार शाम काहिरा एयरपोर्ट पहुंचे। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट को चीन और मिस्र के झंडों से सजाया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और सैन्य गार्डों ने रेड कार्पेट समारोह के साथ उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बुधवार को बातचीत करने का कार्यक्रम है। शी जिनपिंग ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का भी दौरा करेंगे, जो गीजा के पिरामिडों के पास स्थित है। यह मिस्र की उनकी करीब एक दशक बाद पहली यात्रा है। वहीं, 2022 में सऊदी अरब दौरे के बाद यह पश्चिम

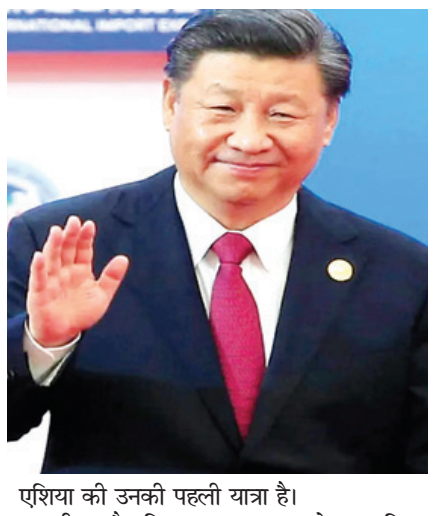

एशिया की उनकी पहली यात्रा है।

चीन और मिस्र इस साल अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसी मौके पर दोनों देशों के नेताओं ने मंगलवार को मिस्र के सरकारी अखबारों में दोस्ताना लेख भी प्रकाशित किए। शी जिनपिंग ने दोनों देशों से विकास के जरिए व्यावहारिक सहयोग का दायरा बढ़ाने की अपील की। वहीं, अल-सीसी ने मिस्र में चीन के निवेश की सराहना की और ताइवान को चीन का हिस्सा मानने वाले बीजिंग के दावे के समर्थन को दोहराया। मिस्र चीन के साथ बढ़ते रिश्तों को अपनी रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने के अवसर के तौर पर देखता है।

मिस्र को 2023 में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख मंच है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसके एक साल बाद मिस्र और चीन ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह पहल दुनियाभर में बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क के निर्माण के जरिए चीन की आर्थिक और रणनीतिक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चीन मिस्र में 10 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुका है। इनमें काहिरा के पूर्व में बिजनेस हब और नील डेल्टा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक रेल लाइन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 20 अरब डॉलर का बताया जाता है। इसके मुकाबले 2025 में अमेरिका और मिस्र के बीच व्यापार 15.7 अरब डॉलर रहा था। चीन लंबे समय से पश्चिम एशिया में अपनी कूटनीतिक और आर्थिक भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

चिंता: कभी जंग के लिए दांव पर लगा दी थी जान, अब इस्राइली हमलों के नतीजों को देखकर अफसोस जता रहे पूर्व जनरल

तेल अवीव, एजेंसी। कभी गाजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ युद्धों में इस्राइली सेना का नेतृत्व करने वाले पूर्व जनरल और खुफिया अधिकारी अब अपने ही देश की नीतियों से खफा नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहूदी आतंकवाद एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस्राइल के सामने सबसे बड़ा खतरा बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों और चरमपंथियों से है, जिन्हें सरकारी शह मिल रही है।

सेवानिवृत्त मेजर जनरल इयाल बेन-रौवेन समेत कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हाल ही में इस्राइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लूटे और ध्वस्त कर दिए गए फलस्तीनी स्कूलों को देखा। साथ ही, उन इलाकों का भी जायजा लिया, जहां यहूदी बस्तियों के लोगों की ओर से फलस्तीनियों को प्रताड़ित करके उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। जनरल बेन-रौवेन ने भावुक होकर कहा कि यहूदी बस्तियों के लोगों की ऐसे हरकतें ईरान, गाजा या लेबनान से भी बड़ा और वास्तविक खतरा हैं। इस दौरे का नेतृत्व करने वाले सेवानिवृत्त जनरल याकूब (79) ने इसे स्पष्ट तौर पर जातीय सफाया करार दिया। एयरफोर्स के पूर्व जनरल असाफ एगमोन ने इसकी तुलना यहूदियों के ऐतिहासिक नरसंहार से करते हुए कहा, भले ही इसका पैमाना अलग हो, लेकिन वेस्ट बैंक से फलस्तीनी अस्तित्व को मिटाने का यह प्रयास उसी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब कोई समाज इस तरह के कृत्यों पर उतर आता है, तो उसका पतन तय है। अक्तूबर 2023 के हमास हमलों के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा और तनाव लगातार बढ़ा है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनः दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज, गुटेरेस आएंगे

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। भारत की मेजबानी में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस भी हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि गुटेरेस के सम्मेलन में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख करीब 10 दिन बाद नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में भाग लेंगे।

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेस का इस साल भारत का यह दूसरा महत्वपूर्ण दौरा होगा। फरवरी 2026 में वह नई दिल्ली में आयोजित इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए थे। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक द्ध शिखर सम्मेलन था। इससे पहले बिश्केक में एससीओ समिट के दौरान गुटेरेस ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ईरान में जारी संघर्ष के मानवीय और आर्थिक प्रभावों पर चिंता जताई।

गुटेरेस ने संघर्ष का समाधान बातचीत और वार्ता के जरिए करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण सम्मान की बात कही, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का

सम्मान भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने व्यापक और स्थायी समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

कौन-कौन से बड़े नेता पहुंच सकते हैं दिल्ली: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शामिल होने की उम्मीद है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी सम्मेलन में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नई दिल्ली में होने वाली यह बैठक वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य और साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ-साथ आउटरीच के तहत आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को थीम बनाया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन बैठकों का उद्देश्य राजनीतिक एवं सुरक्षा, आर्थिक एवं वित्तीय तथा सांस्कृतिक और जन-जन के संपर्क जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में इस समूह की अध्यक्षता कर चुका है।

संपादकीय

युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं

युद्ध जान-माल, अर्थव्यवस्था और शांति के लिए विनाशकारी है। रूस-यूक्रेन व पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा संकट पड़ा है। भारत संवाद व कूटनीति से शांति का समर्थक है। युद्ध मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इतिहास गवाह है कि किसी भी युद्ध ने समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय नई जटिलताओं को जन्म दिया है। अपनी जीत का डंका बजाने वाला देश भी वास्तव में बहुत कुछ खो देता है। युद्ध के परिणाम जान-माल की भारी क्षति, आर्थिक बर्बादी, विस्थापन और सामाजिक अस्थिरता के रूप में सामने आते हैं। यह केवल दो देशों या दो पक्षों के बीच सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर सीमाओं को पार कर अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करता है। रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष इसके उदाहरण हैं। इनसे बनी परिस्थितियों से पता चलता है कि आज की परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक व्यवस्था में किसी एक क्षेत्र की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

भारत हमेशा वैश्विक शांति का समर्थक रहा है और युद्ध के बजाय महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलने का संदेश देता रहा है। इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतहीन युद्ध के बजाय इसके अंत की ओर बढ़ने की वकालत की। गौरतलब है कि पिछले करीब साढ़े चार वर्षों से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। रूस दुनिया के

प्रमुख तेल, गैस और उर्वरक उत्पादक देशों में से एक है, जबकि यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी जैसे कृषि उत्पादों का महत्त्वपूर्ण निर्यातक रहा है। मगर युद्ध के कारण इन वस्तुओं का उत्पादन, परिवहन और निर्यात प्रभावित हो रहा है। काला सागर के रास्ते अनाज की आपूर्ति में रुकावट ने कई देशों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। यह क्षेत्र ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है। होर्मुज जलमार्ग को बंद किए जाने से तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है, जिससे भारत समेत कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है।

संघर्ष के इन मोर्चों से समुद्री मार्गों में जोखिम बढ़ा है और जहाजों के लंबे वैकल्पिक रास्ते अपनाने से माल ढुलाई की लागत भी बढ़ी है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि युद्धकाल का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम नई आशा, उत्साह और समाधान की ओर ले जाता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि भारत अपनी ओर से रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों को समाप्त करने के लिए हर संभव एवं जरूरी कदम उठाने को तैयार है, क्योंकि इसका वैश्विक समुदाय पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इन संघर्षों के बहुआयामी प्रभाव पर नजर डालें, तो इनसे विश्व की भू-राजनीति में भी हलचल पैदा हुई है। अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और पश्चिम एशिया के देशों के बीच संबंधों में नए समीकरण बन रहे हैं। हालांकि, भारत ने रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखा है तथा वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेश नीति तय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्कूलों में कब रुकेगा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला?

कई स्तर पर प्रशिक्षण हासिल कर शिक्षक बनने के बावजूद यह समझना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर किसी बात पर दंडित किया जाता है, तो उसके कोमल मन-मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ता है। इस संबंध में दुनिया भर में न जाने कितने अध्ययन सामने आ चुके हैं कि स्कूली बच्चों को किसी भी रूप में प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। देश में सभी शिक्षक इसके लिए न केवल शैक्षिक दायित्व के मुताबिक, बल्कि कानूनी रूप से भी बाध्य हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि कुछ शिक्षकों को बच्चे की किसी गलती का समाधान सिर्फ उन्हें अलग-अलग तरह से दंडित या प्रताड़ित करने में ही क्यों नजर आता है। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में एक सरकारी स्कूल में ग्यारह साल की बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी कक्षा की किताबें ले जाना भूल गई थी। सिर्फ इसलिए शिक्षिका ने उसे कक्षा में पीछे हाथ ऊपर कर खड़े होने की सजा दे दी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान कुछ दिन बाद मौत हो गई। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी एक छह वर्षीय बच्चे को होमवर्क न कर पाने पर शिक्षिका ने पीटा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मंगलवार को हरियाणा के फरीदाबाद में सिर्फ बिरयानी खाने के सवाल पर एक छात्रा को चार घंटे तक खड़ा रहने की सजा दी गई। खबरों के मुताबिक, इससे आहत होकर उसने स्कूल की छत से कूद कर जान दे दी। सवाल है कि कई स्तर पर प्रशिक्षण हासिल कर शिक्षक बनने के बावजूद यह समझना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर किसी बात पर दंडित किया जाता है, तो उसके कोमल मन-मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ता है। शिक्षण के नियम-कायदों से लेकर शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देश इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। हैरानी की बात है कि कुछ शिक्षक इन नैतिक और कानूनी तकाजों को ताक पर रख कर स्कूल परिसर में भी अपनी विचित्र कुंठाओं से संचालित होते हैं और बच्चों को अलग-अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जिन पर कक्षा में प्रताड़ित किए जाने का घातक असर पड़े। अगर एक शिक्षक को स्कूल में किसी बच्चे की चूक में सुधार की जरूरत महसूस होती है और इसके लिए वह उसे दंडित करना ही एकमात्र उपाय मानता है, तो क्या यह उसके व्यक्तित्व, विवेक, प्रशिक्षण और जिम्मेदारी में कमी का सूचक नहीं है?

आज का कार्टून

भारत के सामने खाद्य सुरक्षा की नई चुनौती

इक्कीसवीं सदी में जिस देश के पास उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त और स्वच्छ पानी, स्वस्थ किसान तथा हर नागरिक तक पौष्टिक भोजन की पहुंच होगी, वही आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत होगा। भारत ने अनाज उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब अगली मंजिल बेहतर थाली की है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि देश कितना अनाज पैदा करता है, बल्कि यह कि क्या हर भारतीय को संतुलित, सुरक्षित, पौष्टिक और सस्ता भोजन उपलब्ध है। भारत को खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण, किसान और पर्यावरण- इन तीनों की सुरक्षा को एक साथ साधना होगा। आखिरकार खाद्य संकट केवल खेत-खलिहान का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न है।

सुनिधि मिश्रा

वैश्विक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और दुनिया में बढ़ते युद्धों ने केवल अर्थव्यवस्था, महंगाई, पर्यावरण और ऊर्जा संकट को ही गहरा नहीं किया है, बल्कि खाद्य संकट को भी एक नई चुनौती के रूप में सामने ला दिया है। खाद्य संकट अब केवल भूख का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास से भी जुड़ गया है। बढ़ती आबादी, सीमित संसाधनों और महंगाई के दबाव के कारण करोड़ों लोगों की थाली तक सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए खाद्य सुरक्षा को अब केवल अनाज की उपलब्धता के बजाय उत्पादन, पहुंच, क्रय-शक्ति और वितरण से जुड़ी व्यापक चुनौती के रूप में समझना होगा।

हाल के वर्षों में युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों ने खाद्य संकट का एक नया चेहरा दिखाया है। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध से पहले रूस और यूक्रेन गेहूं, सूरजमुखी तेल और मक्के के प्रमुख निर्यातकों में शामिल थे। युद्ध ने उत्पादन और निर्यात दोनों को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर दबाव बढ़ा। 'सेंटर फार स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' के जून 2026 के विश्लेषण के अनुसार, युद्ध के चार साल बाद भी यूक्रेन का 2025 का अनाज निर्यात 2020 की तुलना में लगभग 35 फीसद कम रहा। रूस के महत्त्वपूर्ण उर्वरक निर्यातक होने के कारण युद्ध का असर कृषि लागत पर भी पड़ा। पश्चिम एशिया के संघर्षों ने समुद्री व्यापार मार्गों को जोखिम में डालकर खाद्य आपूर्ति की अनिश्चितता और बढ़ा दी है।

इन परिस्थितियों ने दुनिया की सरकारों को यह सोचने पर विवश किया है कि खाद्य सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की पांच एजंसियों द्वारा जारी रिपोर्ट 'विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2026' के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया की करीब 7.8 फीसद आबादी यानी लगभग 64.5 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे थे। यह आंकड़ा लगातार तीसरे वर्ष घटा है। वर्ष 2024 में यह 8.1 फीसद और 2022 में 8.6 फीसद था। हालांकि इस सुधार को स्थायी उपलब्धि मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पौष्टिक भोजन की कीमत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में एक पौष्टिक थाली की औसत वैश्विक कीमत लगभग 4.28 डालर प्रतिदिन हो गई, जबकि 2017 में यह 2.94 डालर थी।

अप्रैल 2026 में जारी 'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' भी चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार 47 देशों में लगभग 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। पहली बार एक ही वर्ष में गाजा और सूडान में अकाल जैसी स्थितियां सामने आईं। स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट का स्वरूप एक समान नहीं है। दक्षिण एशिया और लातिन अमेरिका में स्थिति में कुछ सुधार दिखता है, लेकिन अफ्रीका और पश्चिम एशिया के अनेक हिस्सों में संकट लगातार गहरा रहा है। ऐसे में भारत की स्थिति उपलब्धि और चुनौती, दोनों का मिश्रण है।

गौरतलब कि भारत में कुपोषित लोगों का अनुपात 2004-06 के 21.1 फीसद से घटकर 2023-25 में

9.8 फीसद रह गया है। इस अवधि में कुपोषित लोगों की संख्या भी लगभग 24 करोड़ से घटकर 14.25 करोड़ रह गई। दो दशकों में हुआ यह सुधार निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर 2025 में भारत की करीब 35.5 फीसद आबादी, यानी 52 करोड़ से अधिक लोग पौष्टिक और संतुलित भोजन का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थे। यह आंकड़ा 2017 के 59.8 फीसद से कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी काफी बड़ा है। भारत में पौष्टिक भोजन की अनुमानित कीमत 2025 में करीब 4.11 डालर प्रतिदिन रही।

यहीं भारत के खाद्य संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देश में अनाज की कमी नहीं है, लेकिन संतुलित पोषण की कमी अब भी गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 35.5 फीसद बच्चों का कद उनकी उम्र के अनुपात में कम है और 19.3 फीसद बच्चे कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर, महिलाओं में रक्ताल्पता और शहरी क्षेत्रों में बढ़ता मोटापा एक अलग चिंता पैदा कर रहे हैं। सस्ता और अधिक प्रसंस्कृत भोजन कई परिवारों के लिए मजबूरी बन रहा है। परिणामस्वरूप भारत एक साथ अल्पपोषण और मोटापे के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है।

गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नवंबर 2025 के अंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में देश ने करीब 35.77 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया। चावल और गेहूं का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचा रही है। इसलिए भारत की मूल चुनौती अब केवल अधिक अनाज पैदा करना नहीं, बल्कि हर परिवार की थाली में विविधता और पोषण सुनिश्चित करना है।

इस चुनौती की जड़ें कई स्तरों पर फैली हैं। खाद्य महंगाई, डीजल और उर्वरकों की बढ़ती लागत तथा दालों और तिलहनों के आयात पर निर्भरता कृषि व्यवस्था पर दबाव डालती है। गरीबी और आय की असमानता यह तय करती है कि परिवार आय का कितना हिस्सा पौष्टिक भोजन पर खर्च कर सकता है। गांव और शहर के बीच की आर्थिक दूरी भी भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। वहीं, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़, भूजल का अत्यधिक दोहन और मिट्टी की घटती उर्वरता भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे हैं।

इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में किसान है। अगर खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है, तो किसान की आर्थिक सुरक्षा को उससे अलग नहीं किया जा सकता। छोटे और सीमांत किसानों के लिए बीज, खाद, डीजल और सिंचाई की बढ़ती लागत के साथ मौसम का जोखिम तथा बाजार में कीमतों की अनिश्चितता बड़ी चुनौती है। फसल बीमा, बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाओं और डिजिटल बाजार तक पहुंच को मजबूत करना जरूरी है। किसान की आय स्थिर होगी, तो कृषि उत्पादन भी अधिक टिकाऊ बनेगा और देश की खाद्य सुरक्षा की नींव मजबूत होगी।

आगे का रास्ता स्पष्ट है। भारत को जलवायु-अनुकूल कृषि, सूखा और गर्मी सहने वाली फसल किस्मों, सटीक खेती तथा स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा। मिलेट्स यानी मोटे अनाजों, दालों और स्थानीय अनाजों को बढ़ावा देना पोषण और पर्यावरण, दोनों के लिए उपयोगी होगा। इसके साथ, बेहतर भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश, आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना और भोजन की बर्बादी कम करना भी आवश्यक है। स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूत किए बिना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है।

इक्कीसवीं सदी में जिस देश के पास उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त और स्वच्छ पानी, स्वस्थ किसान तथा हर नागरिक तक पौष्टिक भोजन की पहुंच होगी, वही आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत होगा। भारत ने अनाज उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब अगली मंजिल बेहतर थाली की है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि देश कितना अनाज पैदा करता है, बल्कि यह कि क्या हर भारतीय को संतुलित, सुरक्षित, पौष्टिक और सस्ता भोजन उपलब्ध है। भारत को खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण, किसान और पर्यावरण- इन तीनों की सुरक्षा को एक साथ साधना होगा। आखिरकार खाद्य संकट केवल खेत-खलिहान का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न है।

शहर में सिकुड़ती बच्चों की दुनिया

जब बच्ची दो साल की हो जाए और चलना शुरू कर दे, तो आमतौर पर उसकी उत्सुकता घर से बाहर निकलने की होती है। दरवाजा खुलते ही वह बाहर की दुनिया को जान लेना चाहती है। मां-पिता उसकी सुरक्षा या उससे प्यार, वजह कोई भी हो, चाहते हैं कि उसके सिर कोई अनजान जोखिम न आए। मगर बच्ची के दिमाग में जो चल रहा होता है, वह अपने आप ही दरवाजे के बाहर निकलने और समझने की कोशिश शुरू कर देती है। हालांकि घर से बाहर निकलते ही उसका सामना सामने खड़ी मोटर साइकिलों से होता है।

संदीप विहान

उसका चलना अभी दुनिया को जानने का नया अनुभव होता है। उसके चलने की जगहों में आमतौर पर मां या पिता साथ होते हैं। मां या पिता का साथ एक तरह से बच्ची पर निगरानी की शक्ल में होता है, जिसे खयाल रखने या फिक्र करने के तौर पर जाना जाता है। शहर में सभी नागरिकों को चलने के लिए खुली गलियां नसीब नहीं होती। शहर की संरचना में एक तयशुदा ढांचे में ऊपर से नीचे का क्रम है। किसी के चलने के लिए खुली गलियां है और किसी के लिए तंग गालियां। मगर इस सवाल पर सोचने वाला पिता भी उन्हीं तंग गलियों में बच्ची का हाथ पकड़े और कभी उसे अपने कंधों पर लिए रास्ते नापता रहता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं, तो हमें आम इंसानों के अलावा दो-तीन तरह के जीव ही देखने को मिलते है। इनमें कुत्ते, गाय और कबूतर जैसे जीव शामिल हैं। कभी-कभी इस सूची में बंदर, गिलहरी और छिपकली भी शामिल हो जाते हैं। यानी बच्ची के घर से बाहर की दुनिया के शुरुआती यथार्थ अनुभव में चारों तरफ कंक्रीट की संरचनाएं और मशीनें होती हैं तथा कुछ जीव देखने को मिलते हैं। थोड़ा और बाहर जाने पर इस दुनिया में सड़क पर

भागती-दौड़ती और हार्न बजाती गाड़ियों की दुनिया भी शामिल हो जाती है। सच यह है कि हमारे शहर के व्यस्त और तंग इलाके एक बच्चे के सीखने और जानने के शुरुआती कर्म में किस तरह एक नीरस अनुभव के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस नीरसता को तोड़ने और उसकी दुनिया को विस्तार देने के लिए एक पिता को अपनी बेटी को शहर में दूर एक पार्क में ले जाना पड़ता है। वहां वह घास को छूकर देखती है, पेड़-पौधों को देखती है और कीट पतंगों के पीछे भागती है। हालांकि ऐसा वह घर पर भी करती है। इस प्रक्रिया में चीजों को छूकर, देखकर और टटोलकर प्रकृति के साथ अपने अनुभव संसार का विस्तार करती है। मगर उसके इस अनुभव संसार में सिर्फ वस्तुएं नहीं होतीं, बल्कि एक जीवंत संसार होता है। रवींद्रनाथ ठाकुर बच्चे के जिस स्वतंत्र अनुभव की बात करते हैं, उसका माध्यम प्रकृति से प्रत्यक्ष जुड़ाव है, जिसमें ज्ञान रटाए जाने की अपेक्षा स्वतंत्र और प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा है। एक सवाल जो बार-बार किसी के मन में आ सकता है कि बच्चे प्रकृति और उसमें खेलने के रोमांच से वंचित क्यों हैं? जबकि बचपन की दुनिया में प्रकृति और खेल महत्त्वपूर्ण होते हैं। बच्चे की सीखने-जानने की दुनिया से प्रकृति और खेल का अटूट रिश्ता होता है। बच्चे अपनी प्रकृति को देखकर और उस माहौल में खेलकर स्फूर्ति का अहसास करते हैं और उनके सीखने के अनुभव गहरे और अटूट होते हैं। बंद कमरे और तंग गलियों की जगह प्रकृति खुली किताब की तरह होती है। खुले प्राकृतिक वातावरण में एक बच्ची कीट-पतंगों के पीछे दौड़कर, भागकर, चीजों को छूते हुए, मिट्टी और घास पर गिरते और उठते हुए इन सबको महसूस करती है। प्रकृति और खेल के साथ उसका यह जुड़ाव सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह इन गतिविधियों के माध्यम से अपने शरीर, अपने आसपास के वातावरण और दूसरे जीवों के साथ मनुष्य के संबंध को जानती और समझती है। यह बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया के बुनियादी अंगों में से एक है। अफसोस कि विकास की जिस परिभाषा के चलते शहरों की संरचनाएं खड़ी हुई हैं और उसके फलस्वरूप उनमें जिस तरह की असमानताएं मौजूद हैं, उसमें बच्चे के सीखने की दुनिया लगातार सिकुड़ती नजर आती है। विकास की इस प्रचलित परिभाषा में सड़कों, मकानों, दुकानों और वाहनों आदि के लिए तो जगह है, लेकिन वहां आजाद चलने, खेलने, बैठने और प्रकृति से मिलने की जगहों की कमी नजर आती है। शहर की संरचना में निहित स्थानिक असमानताएं यह तय करती है कि बच्चे का अनुभव संसार कैसा बनेगा और आगे चलकर वह दुनिया को कैसे देखेगा और बुनेगा। बच्चे के लिए पर्यावरण के बारे में रुककर सोचने के लिए उसके अनुभव जगत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अगर वह शहरों में कंक्रीट की इमारतों और गलियों में संरचनात्मक असमानता देखते हुए बड़ा होगा और उसके प्राथमिक समाजीकरण में प्रकृति का खुलापन नहीं होगा, तो आगे चलकर वह अपनी दुनिया से मिले अनुभव के अनुसार ही नई दुनिया रचेगा। यह वैसा ही है, जैसा हम बच्चे को शेर, हाथी, हिरण और अन्य जानवरों के खिलौने उसे दिखाते हैं और उनकी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन असलियत में बड़े होते बच्चे उन्हें देख नहीं पाते। और एक दिन किताबों से उन्हें पता चलता है कि ये सारे जीव या तो लुप्तप्राय हैं या फिर संरक्षण के द्वारा उनको बचाने की कोशिश भर की जा रही है या फिर वे किसी चिड़ियाघर में उनके मनोरंजन का हिस्सा मात्र है।

भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम घोषित

हैंड्सकॉम्ब, सैम कोंस्टास को मौका

नई दिल्ली । क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत ए टीम के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय, और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम की घोषणा कर दी गई है। पीटर हैंड्सकॉम्ब को ऑस्ट्रेलिया ए टीम में जगह मिली है। इससे उनके टेस्ट करियर को एक और मौका मिल सकता है। टीम में ब्रेंडन डॉगेट और झाई रिचर्डसन भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ए इस महीने के आखिर में दौरे के चार दिवसीय मैचों के लिए पुडुचेरी जाएगी, जिसके बाद तीन 50-ओवर के मैच होंगे। भारत ए के खिलाफ सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले दौरे पर आ रहे कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास सीनियर टीम में जगह बनाने का यह मौका है। 35 साल के हैंड्सकॉम्ब चार दिन की टीम में सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी खिलाड़ी

हैं। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पिछले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टूर के सभी चार टेस्ट में खेलने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और न ही ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला है। आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया के भारत लौटने के साथ, यह टूर उन्हें सीनियर टीम में वापसी की दावेदारी का मजबूत मौका देता है। ऑस्ट्रेलिया सबकॉन्टिनेंटल कंडीशन के लिए अपने तेज गेंदबाजी विकल्प को देख रहा है, इसलिए डॉगेट और रिचर्डसन पर भी ध्यान देने की संभावना है। रिचर्डसन कंधे की कई बड़ी सर्जरी के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लौटे हैं, जबकि टॉड मर्फी, सैम कॉन्स्टास और नाथन मैकस्वीनी उन नौ खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पिछले साल लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के चार-दिवसीय मैचों से लौटे हैं। युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन स्पेंसर जॉनसन के साथ वन-डे टीम में हैं।'

आईसीसी रैंकिंग

विमेंस एशिया कप में ऑलराउंडर प्रदर्शन, टी20 करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचीं अट्टापट्टू

दुबई । विमेंस एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के साथ श्रीलंकाई कप्तान चामरी अट्टापट्टू आईसीसी विमेंस टी20 प्लेयर रैंकिंग में तीनों कैटेगरी में अपने करियर की बेस्ट रेटिंग प्वाइंट्स तक पहुंच गई हैं। अट्टापट्टू ने 29 अगस्त को यूएई के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने 25 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए। बतौर गेंदबाज 3 ओवरों में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कप्तान के इस प्रदर्शन की बदौलत टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इस नतीजे से अट्टापट्टू बल्लेबाजों की रैंकिंग में 734 रेटिंग प्वाइंट्स, गेंदबाजों में 552 और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 405 प्वाइंट्स के साथ अपने करियर की सबसे बेहतरीन स्थिति में

पहुंच गईं। वह टी20 बल्लेबाजों में छठे स्थान पर बनी हुई हैं, जबकि गेंदबाजी सूची में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंच गई हैं और ऑल-राउंडर्स में तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। अट्टापट्टू का यह प्रदर्शन इस साल की शुरुआत में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद आया है, जहां उन्होंने श्रीलंका के लिए 172 रन बनाए थे और तीन विकेट लिए थे। उनकी ओपनिंग पार्टनर इमेशा दुलानी ने भी लेटेस्ट अपडेट में काफी सुधार किया है। यूएई के खिलाफ 18 गेंदों पर 25 रन की पारी खेलने वाली दुलानी चार स्थान ऊपर चढ़कर 625 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 18वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। वहीं, हर्षिता समरविक्रमा बल्लेबाजों में एक स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर आ गई हैं। श्रीलंकाई गेंदबाजों को भी टूर्नामेंट के अपने शानदार ओपनिंग मैच का फायदा मिला है। मिताली अयोध्या ने 14 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे यूएई का स्कोर 79 रन तक सीमित रहा और वह 18 स्थान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गईं; साथ ही उनके 444 प्वाइंट्स भी उनके करियर का बेस्ट स्कोर है।

काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश काउंट टीम

सरे से जुड़े औकिब नबी

फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे 3 मुकाबले

नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय टीम में चुने गए तेज गेंदबाज औकिब नबी काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश काउंटी टीम 'सरे' से जुड़ गए हैं, जिसके लिए 3 मैच खेलेंगे। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने टूर्नामेंट में 60 विकेट लिए और जम्मू-कश्मीर को उसका पहला खिताब जिताने में मदद की। नबी अब सरे के लिए यॉर्कशायर, ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ होने वाले अगले तीन मुकाबलों में खेलेंगे। 'आईएएनएस' ने 28 अगस्त को खबर दी थी कि नबी के रविवार को सरे से जुड़ने और काउंटी चैंपियनशिप में खेलने की संभावना है। नबी सरे के लिए तीन मैच खेलेंगे, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को 'द ओवल' में यॉर्कशायर के खिलाफ मैच से होगी। इसके बाद क्रमशः 8 और 15 सितंबर को होव और 'द ओवल' में ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ मैच होंगे।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रविवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'हां, सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद औकिब को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा मिल गया है। माना जा रहा है कि वह आज नई दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह 2 सितंबर से शुरू होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस दौरे का मुख्य मकसद भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए यह देखना भी है कि क्या नबी इंग्लैंड में गेंद को अच्छी तरह से स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें रेड कूकाबुरा गेंद के साथ अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा करने की जरूरत होगी।'

नबी को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह के स्थान पर चुना गया था, हालांकि उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत दोनों मुकाबलों में दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था।

विमेंस डीपीएल

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को हराया

नई दिल्ली । विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ 2 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। अब दोनों टीमें फाइनल मैच में बुधवार को फिर से आमने-सामने होंगी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए 5 विकेट खोकर 126 रन बनाए।

ओपनर नजमा 2 रन पर आउट हो गई, जबकि शिवी शर्मा 3 रन पर आउट हुईं, जिससे टीम 12/2 के स्कोर पर दबाव में आ गई। इसके बाद कप्तान आयुषी सोनी ने 55 गेंदों पर नाबाद 62 रनों की अहम पारी खेली और सात चौकों की मदद से पारी को संभाला। अर्चना ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर टीम को जरूरी गति दी, जबकि समायरा राघव ने 26 गेंदों पर 32 रनों का अहम योगदान दिया, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए रूपाली विश्व मोहन ने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। इनके अलावा, मयूरी सिंह, तनिषा सिंह और एकता भड़ाना ने 1-1 विकेट निकाला। 126/5 के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अनुशासित गेंदबाजी की और तनावपूर्ण आखिरी ओवर में संयम बनाए रखते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 124/7 के स्कोर पर रोक दिया। भले ही साउथ दिल्ली की शुरुआत ठीक रही, लेकिन टीम के लिए कोई निर्णायक साझेदारी नहीं हुई।

प्रिया पुनिया ने 30 गेंदों पर सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि तनीषा सिंह ने 24 रन और कप्तान श्वेता सहरावत ने 12 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली।

वैभव, अभिमन्यु के साथ चमके मुकेश

'सेंट्रल' को 4 विकेट से हराकर फाइनल में 'ईस्ट जोन'

बेंगलुरु । ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के 'सेमीफाइनल-1' में सेंट्रल जोन के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। कुल 7 विकेट हासिल करने वाले मुकेश कुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। अब फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 6 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें ईस्ट जोन की भिड़ंत सेमीफाइनल-2 (नॉर्थ जोन बनाम साउथ जोन) की विजेता टीम से होगी। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 266 रन बनाए। इस पारी में रिंकू सिंह ने सर्वाधिक 60 रन जड़े, जबकि आर्यन जुयाल ने 46 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, यश ठाकुर ने नाबाद 30 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से मुकेश कुमार (56/3) और अभिजीत सरकार ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद शमी और कौनेन कुरैशी ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके जवाब में ईस्ट जोन भी अपनी पहली पारी में 266 रन ही बना सकी। सलामी जोड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 153 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की। वैभव 81 गेंदों में 7 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिमन्यु ने 8 चौकों के साथ 69 रन की पारी खेली। इनके अलावा सुदीप कुमार ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से हर्ष दुबे ने 4 विकेट झटके। आर्यन पांडे और यश ठाकुर को 3-3 विकेट हाथ लगे। सेंट्रल जोन की दूसरी पारी 158 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 97 के स्कोर तक 8 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अरशद खान ने हर्ष दुबे के साथ 9वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शर्मनाक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की। हर्ष 3 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अरशद (25) ने यश ठाकुर (नाबाद 4) के साथ 18 रन जोड़े। इस पारी में मुकेश कुमार ने 44 रन देकर 4 विकेट निकाले। इनके अलावा, मोहम्मद शमी ने 3 शिकार किए।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित

वैभव को मौका, बुमराह भी शामिल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए मंगलवार को 15-सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तानी सौंपी गई है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से भारतीय टी20 टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने पिछले मौके को बखूबी भुनाया था। इस टीम में नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा को फिटनेस के आधार पर शामिल किया गया है, लेकिन मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला। टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे नियमित खिलाड़ी शामिल हैं। हर्षित राणा की भी टीम में वापसी हुई है, जबकि जुलाई में जिम्बाब्वे में खेलने वाली टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में न चुने जाने के बाद संजू सैमसन की वापसी हुई है। नियमित तेज गेंदबाजों की वापसी से गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव हुए हैं। अर्शदीप के साथ बुमराह और हर्षित शामिल हैं। प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव, जो सभी जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम का हिस्सा थे, इस बार टीम में जगह नहीं बना सके। हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह नहीं मिली है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर को दूसरा मुकाबला आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाना है। तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2026 में अपना जलवा बिखेरा है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 और 40 रन की पारियां खेली थीं।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टी-20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*।

पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन पिछले 70 सालों में सबसे खराब

ये खेल ही क्यों रहे: दानिश कनेरिया

नई दिल्ली । पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर से अपने खराब प्रदर्शन की वजह से चर्चा में है। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड में है। शुरुआती 2 टेस्ट गंवाकर पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से पीछे है। सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट फिर से सवालों घेरे में है। पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का कहना है कि पिछले 70 साल में उन्होंने पाकिस्तान टीम की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। आईएएनएस से खास बातचीत में दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी, टीम चयन, चयनकर्ताओं और प्रबंधन से जुड़े अन्य विषयों पर बात की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा, 'पिछले 70 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्थिति सबसे खराब है। हारना बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के किसी भी खिलाड़ी द्वारा कोई संघर्ष या फिर जूझने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती। यह सबसे बुरी स्थिति है।'

कनेरिया ने कहा, 'पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। खिलाड़ी हों या चयनकर्ता किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है।

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पीसीबी में 'भूचाल'

सेलेक्टर मिस्बाह-उल-हक ने इस्तीफा भेजा

नई दिल्ली । दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद सीरीज के बीच में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम में बड़े बदलाव किए, जिसके बाद मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान की पुरुष चयन समिति के सेलेक्टर पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। मिस्बाह मार्च में बनी उस चार सदस्यीय चयन समिति का हिस्सा थे, जिसमें आकिब जावेद, सरफराज अहमद और असद शफीक भी शामिल हैं। हालांकि, 'क्रिकइन्फो' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने चयन पैनल से इस्तीफा देने की पेशकश की है। पीसीबी ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक मिस्बाह ने लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकादमी में बैटिंग कंसल्टेंट के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सोमवार को पीसीबी ने टेस्ट टीम से 7 खिलाड़ियों के साथ हेड कोच और बॉलिंग कोच सरफराज खान और उमर गुल को हटाया।

ईशांत शर्मा: कपिल देव के बाद टेस्ट में भारत के दूसरे सफलतम तेज गेंदबाज

पांच साल से पहले खेला आखिरी मैच

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को उनकी लंबाई और निरंतरता के साथ 150 के आस-पास की गति के साथ गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। ईशांत टेस्ट क्रिकेट में भारत के छठे सबसे सफल गेंदबाज हैं। वहीं कपिल देव के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं। ईशांत शर्मा का जन्म 2 सितंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2006 में दिल्ली के लिए डेब्यू किया। छह फीट चार इंच लंबे ईशांत शर्मा के पास वह सारी क्षमताएं थी, जो एक तेज गेंदबाज में होनी चाहिए। उनके पास गति के अलावा, स्विंग, और बाउंस था, जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करता था। विराट कोहली, शिखर धवन, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के साथ घरेलू क्रिकेट खेलने वाले ईशांत को मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला। घरेलू क्रिकेट में पदार्पण के ठीक एक साल बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले ईशांत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और जल्द ही टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारतीय तेज गेंदबाजी का

प्रमुख चेहरा बन गए। ईशांत ने देश और विदेश दोनों जगहों पर सफलता प्राप्त की। एमएस धोनी की कप्तानी में 2013 में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी चैंपियस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के ईशांत अहम सदस्य रहे।

शर्मा का व्यापक असर टेस्ट क्रिकेट में दिखा। विराट कोहली की कप्तानी में देश और विदेश में टेस्ट में भारतीय टीम को मिली सफलता की एक वजह ईशांत की गेंदबाजी भी रही। शर्मा भारत के उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्हें 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल हो सकी है।

38 साल के होने जा रहे ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम के लिए 105 टेस्ट मैच, 80 वनडे और 14 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट मैचों में उनके 311, वनडे में 115 और टी20 में 8 विकेट दर्ज हैं। ईशांत नवंबर 2021 के बाद से भारतीय टीम के लिए नहीं खेले हैं।

ईशांत निश्चित रूप से अब भारतीय टीम की योजना में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अब तक संन्यास नहीं लिया है। वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं।

लॉर्ड्स टेस्ट में करारी हार के बाद पाकिस्तान का बड़ा एक्शन

इंग्लैंड दौरे से 7 खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ की छुट्टी, माइक हेसन को कमान

लंदन। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 194 रनों की करारी शिकस्त और सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कड़े कदम उठाए हैं। पीसीबी ने इंग्लैंड दौरे के बीच से ही अपनी लगभग आधी टीम बदलते हुए 7 प्रमुख खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया गया है। टीम से बाहर किए गए 7 खिलाड़ी और उनके रिप्लेसमेंट पीसीबी के आधिकारिक बयान के अनुसार, खराब प्रदर्शन के चलते बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड भेजा जा रहा है।

वापस बुलाए गए खिलाड़ी (7): मोहम्मद रिज़वान, इमाम-उल-हक़, सलमान अली आग़ा, आमिर जमाल, ख़ुर्रम शहज़ाद, अली उस्मान और ओवैस ज़फर।

नए शामिल खिलाड़ी (7): साइम अयूब, अब्दुल्ला फ़ज़ल, अराफ़ात मिन्हास, इमरान जूनियर, साद बेग, इमरान रंधावा और रज़ाउल्लाह।

कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल: माइक हेसन को टेस्ट की भी कमान

सरफराज और उमर गुल की छुट्टी: मुख्य कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल की छुट्टी कर दी गई है।

हेसन और नोफ्के को जिम्मेदारी: सीमित ओवरों (व्हाइट-बॉल) के मुख्य कोच माइक हेसन को अब टेस्ट (रेड-बॉल) टीम का भी मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वहीं एशले नोफ्के को टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया है।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए न्यायाधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यायल नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670